WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा को हुई थी एंजाइटी

वर्षः 01 अंक : 267 | लखनऊ, बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

छोटे शहरों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी

पटना, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को गति देने के लिए 'आत्मनिर्भर बिहार' विशेषकर देश के छोटे शहरों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र की नमामि गंगे और अमरुत योजना से संबंधित बिहार में 543.28 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि शहरी गरीबों और शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए वह सभी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति देने के लिए आत्मनिर्भर बिहार विशेषकर देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ अमरुत मिशन के तहत बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण आज के दौर की सच्चई है। आज पूरे विश्व में शहरी क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। भारत भी इस वैश्विक बदलाव का अपवाद नहीं है, लेकिन कई दशकों से हमारी मानसिकता बन गई और हमने मान लिया था कि शहरीकरण खुद में एक बड़ी समस्या और बड़ी बाधा है लेकिन उनका सोचना कुछ अलग है। यदि शहरीकरण समस्या लगती है तो उसमें अवसर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तो उस दौर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था और वह शहरीकरण के बड़े समर्थक थे। उन्होंने शहरीकरण को समस्या नहीं माना। उन्होंने तो ऐसे शहरों की कल्पना की थी, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवसर मिले और जीवन को बेहतर करने के रास्ते खुलें।

चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सदन में बोले

हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने को तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर सदन में बयान देते हुए कहा कि लद्दाख जाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर हमारे जवानों ने बलिदान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है और इसका हल शांति से निकाला जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 जून को भी गलवान में हिंसक झड़प हुई, हमारे जवानों ने मंशा को भांप लिया था, बहादुर सैनिकों ने अपने शौर्य से चीन को पीछे धकेल दिया और जरूरत के हिसाब से जवाब भी दिया। हमारे वीर सपूतों ने देश का हमेशा ही गौरव बढ़ाया है, हमें जवानों पर मान है। हमारी सेना चुनौतिपूर्ण मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। राजनाथ ने कहा कि हम हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार हैं। सिंह ने कहा कि सीमा पर शांति के लिए दोनों देश सहमत हैं। पूरा देश हमारे वीर जवानों के साथ खड़ा है। बता दें कि राजनाथ की हाल में मास्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे के साथ मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी चीन के उनके समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वांग यी से दो टूक में कहा था कि जब तक एलएसी पर शांति नहीं होती और चीनी सैनिक पूछे नहीं हटते तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।

बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाने पर संजय राउत का कंगना पर हमला, बोले

आरोप लगाने वालों का डोप टेस्ट हो

नई दिल्ली, एजेंसी। बॉलीवुड में ड्रग्स माफ्रियाओं को लेकर सवाल उठाने के मामले में बयानबाजी का दौर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन का समर्थन करते हुए बेबाकी से अपनी बात रखने वाली विवादों में घिरी अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता ने कहा कि जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले उनका ही डोप टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, उसपर बच्चन परिवार जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि आज जया बच्चन ने राज्यसभा में जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है। शिवसेना नेता ने कहा कि कंगना रनौत शिवसेना के आदित्य ठाकरे के बारे में जो भी आरोप लगा रही हैं, उन्हें गृह मंत्रालय, गृह सचिव और एजेंसियों को सबूत देने चाहिए। शिवसेना नेता ने कहा कि जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले उनका ही डोप टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ बुरे लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री को ही बदनाम कर दो। फिल्म उद्योग की कथित आलोचना पर नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि देश में किसी भी संकट के दौरान सहायता में कभी पीछे नहीं रहने वाला यह उद्योग सराहना का हकदार है। उन्होंने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुख की बात यह है कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। जया ने कहा कि केवल कुछ लोगों की वजह से आज मनोरंजन उद्योग आलोचना का शिकार हो रहा है।

कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है

नयी दिल्ली, एजेंसी। हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के किसानों को गुमराह कर आन्दोलन कराने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार किसानों के हितों की हर हालत में रक्षा करेगी। श्री दलाल ने राज्य के किसान संगठनों के साथ मंगलवार को केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस किसानों के बीच मंडी व्यवस्था समाप्त होने का भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह कर रही है और जगह-जगह आन्दोलन करा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को जनादेश नहीं दिया था जिसके कारण वह राज्य में दुष्प्रचार करा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कृषि सुधारों के बावजूद मंडी व्यवस्था कायम रहेगी और किसान पहले की तरह यहां फसलों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि श्री तोमर ने स्पष्ट कहा है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।

प्रदेश में 24 घंटें में कोरोना के संक्रमित 6895 नये केस

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाए, ताकि जांच कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न होता रहे। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि यह कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों की स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करें। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में कोरोना के रोगियों की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लायी जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन सुगमतापूर्वक उपलब्ध रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन निर्धारित मूल्य पर ही मिले। किसी भी दशा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए, उन्होंने कहा कि कालाबाजारी होने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन से संवाद बनाकर कोविड-19 के दृष्टिगत उपचार सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के सम्बन्ध में आमजन को लगातार जागरूक किये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाए। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस द्वारा आपसी समन्वय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम को संचालित किया जाए। कोविड-19 से बचाव तथा यातायात सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से चौराहों तथा बाजार आदि में प्रसारित की जाए। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने बताया कि बाजारों एवं चौराहों पर कोविड-19 के संबंध में आम जनमानस को जागरूक किया जाये। उन्होनें बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी की जानकारी भी आम जनमानस को दी जाये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिये।

स्वास्थ्यकर्मियों की बीमा योजना की अवधि छह माह के लिए बढ़ी

नयी दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर मुस्तैदी से डटे डॉक्टर तथा नर्स सहित सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि को दोबारा छह माह यानी 180 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि 50 लाख रुपये की इस बीमा योजना को 30 मार्च को 90 दिन के लिए लागू किया गया था। इसकी अवधि बाद में 90 दिन और बढ़ाकर 25 सितंबर तक की गयी थी लेकिन आज फिर अवधि में छह माह की बढ़ोतरी कर दी गयी है। इस बीमा पैकेज का लाभ उन स्वास्थ्यकर्मियों को मिलता है , जो कोरोना संक्रमित के उपचार से सीधे जुड़े हैं,भले ही वे डॉक्टर हों, नर्स हों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों या किसी केंद्रीय, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के काल में काम पर रखे गये निजी अस्पताल के कर्मचारी हों।

एनआईए ने एनआईए के एजेंट को किया अरेस्ट पाक भेजता था सैन्य गतिविधियों की जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विशाखापत्तनम जासूसी मामले में एक अहम आरोपी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और उसके लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनआईए के एक अधिकारी के बताया कि गुजरात के गोधरा निवासी 37 वर्षीय गितेली इमरान को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि इमरान जासूसी गतिविधियों में लिप्त था और पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहा था। यह मामला एक अंतरराष्ट्रीय जासूसी रैकेट से जुड़ा है जिसमें पाकिस्तान के जासूसों ने भारत में कई एजेंटो की भर्ती की थी। इसका मकसद भारतीय नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के स्थानों अथवा उनके आवागमन के बारे में और साथ ही अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एकत्र करना था। जांच में यह सामने आया कि नौसेना के कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया ऐप फेसबुक और व्हाट्सऐप के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आए। उन्होंने गोपनीय जानकारी साझा की जिसके लिए भारत में मौजूद आईएसआई के सहयोगियों ने उनके बैंक खातों में धन जमा कराया। इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ15 जून को आरोप पत्र दाखिल किया गया। एनआईए के अधिकारी ने कहा कि इमरान सीमा पार कपड़ा व्यापार की आड़ में पाकिस्तानी जासूसों अथवा एजेंट से जुड़ा हुआ था। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के जासूसों के निर्देशों पर उसने भारतीय नौसेना के कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए संवेदनशील और गोपनीय आंकड़ों के बदले समय समय पर उनके खातों में पैसे जमा किए। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को उसके घर में छापा मारा गया जहां से कुछ डिजिटल साक्ष्य और कुछ दस्तावेज बरामद हुए है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

औद्योगिक विकास को और गति देने की तरफ बढ़ रही योगी सरकार

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी सेवाओं को एक क्लिक (ऑनलाइन) पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में समय सीमा तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर दिलाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सरलीकरण करने को कहा है। उन्होंने सभी विभागों को इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। योगी ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की समीक्षा भी की है और कहा है कि 2016 की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उप्र का प्रदर्शन और बेहतर बनाएं। योगी ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाये गये हैं। इन सुधारों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करते हुए कार्य योजना बनाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सुधारों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं।मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और सुदृढ़ करने को कहा है।

वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी

नयी दिल्ली, एजेंसी। संसद ने मंगलवार को वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी जिसमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रूपये से बढाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। लोकसभा में यह विधेयक बजट सत्र में पारित हुआ था जबकि राज्यसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गयी। इस तरह इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विधेयक पर हुयी चर्चा में कहा कि कुछ सदस्यों ने एटीसी कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया है जबकि हकीकत यह है कि पिछले तीन वर्षों में तीन हजार एटीसी नियुक्त किये गये हैं। हवाई अड्डों का निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको ऐतिहासिक परिदृष्य में देखा जाना चाहिए। वर्ष 2006 में दिल्ली और मुंबई के दो प्रमुख हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप अब तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 29 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद इन दोनों हवाई अड्डों पर यात्री ट्रैफिक में 33 फीसदी की बढोतरी हुयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में छह हवाई अड्डों का निजीकरण करने की तैयारी की गयी । एक हवाई अड्डा के लिए तो सबसे अधिक बोलियां आयी है। इसके लिए पूरी दुनिया की कंपनियों ने बोली लगायी है। उन्होंने कहा कि केरल में एक हवाई अड्डे के निजीकरण को लेकर राज्य सरकार ने भी बोली लगायी थी लेकिन उसकी बोली सबसे ऊंची बोली की तुलना में 93 फीसदी से भी कम थी। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

भारत में कोरोना मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में कमः हर्षवर्धन

नई दिल्ली, एजेंसी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके कारण संक्रमण से मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। डॉ. हर्षवर्धन ने सदन में कोविड महामारी और सरकार के कदम पर एक वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकार इस महामारी का रणनीतिक तरीके से मुकाबला कर रही है और अभी तक सफल रही है। सरकार को कोविड-19 के नये मामले और इससे होने वाली मौतों पर रोक लगाने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को कोरोना संक्रमण के मामलों में देश की स्थिति और इससे लडने के लिए सरकार की रणनीति की जानकारी देते हुए बताया कि देश महामारी से मरने वालों की संख्या कम है और इसके प्रसार को रोकने के लिए उठाए गये कदम सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 13 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं लेकिन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यहां स्थिति ज्यादा बेहतर है। कोरोना के कारण ज्यादातर मामले और मौतें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, केरल,पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा और गुजरात से हैं। सरकार के प्रयास से कोरोना संक्रमण पर रोक लगी है। कोरोना संक्रमितों के मामले भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की चपेट में आये कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48 लाख के पार जा चुकी है जबकि इस वायरस से 79 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 37.7 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर करीब 77.77 फीसदी है।

पांच दिन बाद कोरोना संक्रमण के नये मामले 90 हजार से कम

एक दिन में 83 हजार संक्रमित

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना महामारी की दिनों-दिन विकराल होती स्थिति के बीच कुछ राहत की बात यह रही कि पांच दिन के बाद संक्रमण के 90 हजार से कम नये मामले सामने आये हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इनकी संख्या 83,809 रही। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 83,809 नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 49,30,237 पर पहुंच गया जबकि इससे पहले नौ सितंबर से 13 सितंबर तक कोरोना संक्रमितों की दैनिक वृद्धि 90 हजार से अधिक रही। नौ सितंबर को 95735, दस को 96551, ग्यारह को 97570, बारह को 94372 और तेरह सितंबर को 92071 मामले सामने आये। 94,372 कोरोना संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या 79,292 बढ़कर 38,59,400 हो गयी। स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नये मामले अधिक होने से सक्रिय मामले 3,463 बढ़कर 9,90,061 हो गये हैं। इसी अवधि में 1,054 मरीजों की मौत हो गयी। देश में अब तक 80,776 कोरोना संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में सक्रिय मामले 20.08 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 78.28 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.64 फीसदी है। कोरोना महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और यह 914 बढ़कर 2,91,630 हो गयी तथा 363 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 29,894 हो गया। इस दौरान 15,789 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 7,55,850 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजों की संख्या 1868 कम होने से सक्रिय मामले 93,204 रह गये।

राज्यसभा में तृणमूल ने सोशल डिस्टेंसिंग पर आपत्ति जताई, मराठा मुद्दा गूंजा

नई दिल्ली, एजेंसी। मराठा मुद्दे से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में उठाए गए। कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने शून्यकाल में मराठा समुदाय के आरक्षण पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोटा मुद्दा उठाया। संभाजी छत्रपति ने भी इसी विषय पर बात की। तृणमूल कांग्रेस के सांतनु सेन ने सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे श्सोशल डिस्टेंसिंगश् शब्द पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि इससे कोविड रोगियों और उनके परिवारों को अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ा है। उपराष्ट्रपति और पदेन सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सेन से सहमति जताई और कहा कि इस शब्द की जगह किसी और उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने कोरोना काल में शिक्षा में डिजिटल डिवाइड के मुद्दे को उठाया, वहीं उनके पास बैठे तृणमूल सांसद डेरेक ओ श्ब्रायन ने सहमति जताई। शिवा ने दावा किया कि इसने एक वर्ग को दूसरे के मुकाबले ज्यादा फायदा पहुंचाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने नोएडा का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या के मुकाबले आत्महत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया कि म हामारी के कारण नौकरी गंवाने वालों को 15,000 रुपये प्रति माह की सहायता देने पर विचार करने का आग्रह किया। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने देश में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग किया कि मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य रूप से जीवन बीमा के दायरे में रखा जाना चाहिए।

कश्मीर के पुलवामा में दो जवानों को जख्मी कर भाग निकले आतंकी

जम्मू, एजेंसी। आज दो अलग अलग घटनाओं में दो आतंकी तथा तीन घुसपैठिए आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहे हैं। इनमें से दो आतंकी पुलवामा में कुछ घंटों की मुठभेड़ के बाद भाग निकले। इस मुठभेड़ में दो जवान जख्मी भी हुए हैं। इसी तरह से जम्मू सीमा के सांबा सेक्टर में घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम बनाते हुए बीएसएफने तीन घुसपैठिए आतंकियों को पाकिस्तान वापस धकेल दिया। बीएसएफका दावा है कि तीनों घुसपैठिए जख्मी हुए हैं। पुलवामा के मारवाल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ फिलहाल थम चुकी है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी मौका पाकर मुठभेड़ स्थल से फरार होने में सफल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान दो जवान भी घायल हुए हैं। दोनों घायलों को 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के दिये निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाए, ताकि जांच कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न होता रहे। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि यह कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों की स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करें। मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में कोरोना के रोगियों की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लायी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन सुगमतापूर्वक उपलब्ध रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन निर्धारित मूल्य पर ही मिले। किसी भी दशा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन से संवाद बनाकर कोविड-19 के दृष्टिगत उपचार सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के सम्बन्ध में आमजन को लगातार जागरूक किये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाए। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस द्वारा आपसी समन्वय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम को संचालित किया जाए। कोविड-19 से बचाव तथा यातायात सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से चौराहों तथा बाजार आदि में प्रसारित की जाए। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि धान खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जनपद बिजनौर के गौ-आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के लिए अलर्ट सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि दैवीय आपदा से होने वाली जनहानि में राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य आर्थिक मदद प्रभावितों को समय से उपलब्ध करायी जाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लोकबंधु अस्पताल की बड़ी लापरवाही, डिस्चार्ज के समय मरीज को बताया कोविड संक्रमित

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफ होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। राजधानी लखनऊ में एक मरीज को बिना कोरोना की जांच कराए कोविड हॉस्पिटल भेज दिया गया। कोविड अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं मिली और वह एंबुलेंस में ही 6 घंटे तक तड़पता रहा। बीते दिन एक्सीडेंट होने के बाद मरीज को सहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन आर्थिक तंगी और पैसों की कमी के चलते परिजनों ने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर से रेफर करने की मांग की। जिसके बाद मरीज को लोकबंधु अस्पताल लाया गया। जहां 6 घंटे से अधिक समय तक मरीज को एंबुलेंस में ही रहना पड़ा। लेकिन वहां उसका इलाज करने के बजाय डॉक्टर ने मरीज को बिन देखे ही केजीएमयू या पीजीआई रेफर करने की सलाह दे दी।

डीओपीटी ने दिये आईएएस आईपी पाण्डेय पर कार्यवाही के निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा आईएएस अफसर आईपी पाण्डेय के उपाध्यक्ष, केडीए पद पर नियुक्ति के लिए पैसे देने के मामले में की गयी शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार को कार्यवाही हेतु कहा है। नूतन ने इस संबंध में एसटीएफओं के बाद थाना विभूतिखंड में दर्ज मुकदमे की विवेचना सीबीआई से करवाए जाने तथा आईएएस अफसर श्री पाण्डेय को तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि थाना विभूतिखंड में दर्ज मुकदमे को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में श्री पाण्डेय की स्पष्ट भूमिका है, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। के सी राजू, अवर सचिव, डीओपीटी द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को पत्र भेज कर कहा गया है कि नूतन ने आईपी पाण्डेय द्वारा घूस देने के मामले के शिकायत की है, जिसपर समुचित कार्यवाही की जाये।

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनायेगा, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच

लखनऊ, संवाददाता। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ''पुष्कर'' के आह्वाहन पर केन्द्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण, करोड़ों प्रतियोगी छात्रों के रिजल्ट एवं नियुक्ति की समय सीमा अनिश्चित एवं आये दिन गलत फैसलो से बढ़ती हुई बेतहासा बेरोजगारी के विरूद्ध पूरे देश व प्रदेश में दिनांक 17 सितम्बर, प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को ''राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस'' के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। संगठन पूरे देश व प्रदेश के छात्रों, बेरोजगारों व नौजवानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है, संगठन के प्रयासों से राजनीतिक दलों में युवाओं के प्रति चेतना जागृत हुई है, युवाओं को जाति, धर्म के आधार पर सिर्फ वोट बैंकध्प्रचार तंत्र समझने वाले राजनीतिक दलों को यह अहसास हो चुका है कि देश व प्रदेश का नौजवान अपने अधिकारों, संरक्षण व सवंर्धन हेतु एकजुट हो चुका है। सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी संगठन के उद्देश्यों का अनुसरण करते हुये 21वीं सदी का बेरोजगार, नौजवान अपनी जागरूकता के माध्यम से राजनीतिक दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ही बेरोजगारों, नौजवानों, वंचितों, गरीबों व किसानों की बेहतर आवाज बन सकता है। अतः नौजवान, बेरोजगारहित व जनहित में शशांक शेखर सिंह ''पुष्कर'' जी के उद्देश्यों, विचारों से आम युवाओं व जनता में सकारात्मक व जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 65 से 70 प्रतिशत नौवजवानों को एक एक मंच पर लाकर अपनी ताकत का एहसास कराना वर्तमान में अति आवश्यक है। युवाओं के बगैर 21वीं सदी के भव्य भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चिंता जनक प्रभावी कदम उठाए केंद्र सरकारः मायावती

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कोरोना माहमारी के बीच अस्पतालों में आक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र से तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इस महामारी के विरूद्ध जारी संघर्ष में पीपीई किट के बाद अब खासकर यूपी, बिहार व महाराष्ट्र आदि के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी अति-चिन्ता की बात है। ऐसे में केंद्र तुरंत प्रभावी कदम उठाए ताकि कोरोना से होने वाली बढ़ती मौतों को रोका जा सके।

वार्षिक कैंटोनमेंट बोर्ड में वीडियो सम्मेलन आयोजित

लखनऊ, संवाददाता। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चल रहे राष्ट्रीय अभियान को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक कैंटोनमेंट बोर्ड सम्मेलन, जो सभी 25 छावनी बोर्डों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबधित है, मध्य कमान मुख्यालय में दो दिवसीय वीडियो कांफ्रेंसके रूप में 14 और 15 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य कमान के जीओसी-इन-सी, लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुमन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस में छावनी के प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों ने भाग लिया। छावनी बोर्डों के बजट अनुमानों को तर्कसंगत बनाना, विकास परियोजनाओं का स्टॉक लेना और छावनी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान लागू करना और छावनी बोर्डों द्वारा वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना कांफ्रेंस के मुख्य बिंदु थे। दो दिवसीय कांफ्रेंस के दौरान कोविड के विरुद्ध छावनी में चल रहे अभियान, संशोधित छावनी बोर्ड खाता नियम-2020के क्रियान्वयन, छावनी बोर्ड के डिजिटल ओवर हालिंग, स्वच्छता में सुधार, स्वच्छ भारत सुविधाएं और अनधिकृत निर्माणों की रोकथाम,जैसेकुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

ट्यूशन टीचर ने मासूम को दी तालिबानी सजा, हाथ पीछे बांधकर डण्डे से पीटा

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के मलपुर से एक बच्चे से क्रूरता भरा व्यवहार करने का मामला सामने आया है जहां ट्यूशन पढ़ने गए 8 वर्षीय बच्चे को उसके टीचर ने तालिबानी सजा दी। बच्चे के हाथों को तार से पीछे बांधकर लाठी-डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के कारण बच्चे के पैर, पीठ और कमर पर काफी गहरे चोटे आई हैं। बच्चे के माता पिता ने स्थानीय पुलिस को जाकर इस बात की सूचना दी। जिसके बाद आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, 8 वर्षीय सिद्धार्थ और उसकी बहन ट्यूशन पढ़ने सचिन गुप्ता के यहां जाते हैं। हालांकि सिद्धार्थ थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है। बताया जा है कि टीचर ने बच्चे को होमवर्क दिया था। जो वह करके नहीं लाया इसी बात पर बच्चे को डांटा तो उसने टीचर को दांत काट लिया।

महिलाओं की देश के विकास में भागीदारी बहुत जरूरी

लखनऊ, संवाददाता। महिला कांग्रेस का 37वां स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना एवं महिला कांग्रेस मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी के नेतृत्व में झण्डारोहण किया गया। जिसमें भारी संख्या में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित रहीं। इस मौके पर महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एकत्र महिलाओं को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सबसे पहले मौजूद महिलाओं को बधाई दी। उन्होने कहा कि यहां एकत्र प्रत्येक महिला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रही हैं। प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था और बढ़ते महिला अपराधों के विरूद्ध सड़क पर संघर्ष कर रही हैं। उन्होने महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि महिला कांग्रेस की प्रत्येक महिला राहुल और प्रियंका के संदेश को अमलीजामा पहना रही हैं और अन्याय के खिलाफ जमकर लड़ रही हैं, डटी हुई हैं और पीछे नहीं हट रही हैं। कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए कहा कि महिला कांग्रेस की स्थापना आज के 37 साल पहले इन्दिरा जी ने की थी। उन्होने कहाकि इन्दिरा जी जानती थीं कि महिलाओं को उचित मंच दिये बिना भारत का विकास संभव नहीं है। महिलाओं की देश के विकास में भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होने कहा कि आज के परिवेश में महिलाओं को अन्याय के खिलाफ डटकर मुकाबला करना होगा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ममता चौधरी ने इस मौके पर मौजूद सभी महिलाओं को स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि जिस प्रकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी।

21 को सपा का ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में प्रर्दशन

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आगामी 21 सितम्बर 2020 को समाजवादी पार्टी सभी जनपदों में तहसील स्तर पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि, बेहाल किसान, बेरोजगारी और ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को सम्बोधित ज्ञापन सौपेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार की जनहित विरोधी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ समाजवादी अपनी आवाज उठाते रहे हैं। राज्य सरकार की गलत नीतियों और विरोध को कुचलने के रवैये से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समाजवादी पार्टी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर सरकारी मनमानी, तानाशाही और ध्वस्त कानून व्यवस्था, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में गड़बड़ी आदि समस्याओं पर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने का आग्रह करेगी।

कोरोना का कहर विकराल रूप धारण करता जा रहा है। भाजपा की राज्य सरकार इसकी रोकथाम में असफल साबित हुई है। कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं तथा उपचार नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों में कोरोना से मौतें थम नहीं रही हैं। समाजवादी सरकार के समय की 1090 और 181 महिला हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी भाजपा सरकार खत्म करने जा रही है। अनियोजित लॉकडाउन के दौरान जो लाखों श्रमिक प्रदेश में अपने घर वापस आए, रोजगार के अभाव, आर्थिक तंगी, नौकरी न होने और कारोबार व्यापार बंदी से मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, बुनकर, व्यापारी, छात्र, महिलाएं, अल्पसंख्यक सभी बदहाल हैं। लूट, हत्या, अपहरण की घटनाएं रोज ही घट रही हैं। महिलाओं-बच्चियों से दुष्कर्म और विपक्ष खास कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामलों में सरकार संवेदनशून्य रवैया अपनाती है। उत्तर प्रदेश में अराजकता और जंगलराज का बोलबाला है। अपराधी बेखौफहैं और जनता के जानमाल की सुरक्षा में पुलिसतंत्र विफल है। प्रदेश में फर्जी एनकाउण्टर और हिरासत में मौतों का सिलसिला चालू है। मंहगाई चरम पर है। स्कूल कालेज बंद हैं छात्रों का भविष्य अंधकार में है।

केशव मौर्य ने किया विश्वेश्वरैया द्वार व मल्टीलेटवल पार्किंग का शिलान्यास

लखनऊ, संवाददाता। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा है कि इंजीनियर विश्वेश्वरैया के जीवन से सीख और प्रेरणा लेकर देश व प्रदेश के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने विभाग इंजीनियरों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इंजीनियर विश्वेश्वरैया, श्रीधरन और भाभा जैसे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की परंपरा के वाहक हैं। देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने का काम करें। लोनिवि मुख्यालय स्थित विश्वश्वरैया हाल में आयोजित जयंती समारोह में केशव मार्य ने मंगलवार को यह बातें कहीं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर विश्वेश्वरैया के नाम से एक करोड़ नौ लाख की लागत से बनने वाले भव्य द्वार और 19 करोड़ की लागत से बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग का का निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के प्रथम चरण में रोड कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले इंजीनयरों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सौ कार्मिकों को यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान पाने वालों में अयोध्या, वाराणसी के मुख्य अभियंता राकेश राजवंशी, निर्माण निगम के एमडी सत्यप्रकाश सिंघल, मुख्य अभियंता अशोक अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ताओं में जितेन्द्र कुमार बांगा, अशोक कनौजिया, इरफान अहमद, राकेश सिंह अधिशासी अभियन्ताओं में संदीप सक्सेना, बच्चू लाल सिंह, पियूष द्विवेदी, सहायक अभियन्ता राजीव कुमार राय, अवर अभियन्ता पंकज मौर्या व आरके ओझा के साथ ही कर्मचारियों में नीमा पन्त, रेखा केसरवानी, सर्वेश कुमार, आशीष श्रीवास्तव, जीवानन्द, नवीन त्रिपाठी, संजय चौरसिया, निर्मल मिश्रा, ललित सहवाल, विपिन सिंह, अतुल मौर्या व तुलसी राम को कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र दिया गया।

178 दिनो से बेरोजगार अमीनाबाद के सैकड़ो पटरी दुकानदारो ने मांगी भीख

अमीनाबाद के पटरी दुकानदारो और बड़े दुकानदारो के बीच नही सुलझा विवाद

लखनऊ, संवाददाता। देश मे आए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लाक डाउन से पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का एलान किया था जनता कर्फ्यू तो एक दिन बाद समाप्त हो गया लेकिन 22 मार्च से आज तक अमीनाबाद के करीब एक हजार पटरी दुकानदारो के लिए आज भी जनता कर्फ्यू है क्यूकि 22 मार्च के बाद से लेकर आज 178 दिन बीत गए लेकिन गरीब परिवारो से ताल्लुक रखने वाले अमीनाबाद के पटरी दुकानदारो की दुकाने फुटपाथ पर नही सजी। 178 दिनो से गरीबी बेरोजगारी का दंश झेल रहे सैकड़ो पटरी दुकानदारो ने आज उन्ही दुकानदारो से विरोध स्वरूप भीख मांगी जो दुकानदार पटरी दुकानदारो की दुकानो का विरोध कर रहे है। मंगलवार को अमीनाबाद पटरी दुकानदार वेलफेयर सोसाईटी के अध्यक्ष मनीष चौधरी और महांमंत्री दीपक सोनकर उर्फशैलू सैकड़ो महिला पुरूष पटरी दुकानदारो के साथ सड़क पर उतरे और अपने हाथो मे कटोरा लेकर विरोध स्वरूप उन्ही दुकानदारो से भिक्षा मांगी जो दुकानदार अपनी दुकानो के आगे पटरी दुकाने लगने का विरोध कर रहे है। 178 दिनो से बेरोजगार पटरी दुकानदारो को दोबारा रोजगार दिलाने के लिए संर्घष कर रहे दीपक सोनकर उर्फशैलू ने कहा कि अमीनाबाद क्षेत्र मे करीब 1 हजार पटरी दुकानदार है जो करीब 50 वर्षो से सड़क पर दुकान लगा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे लेकिन कोरोना काल मे जब से जनता कर्फ्यू लगा है तब से करीब 1 हजार पटरी दुकानदारो के रोजगार बन्द है उन्होने बताया कि करीब 6 महीने का समय बीत गया है लेकिन न सरकार ही पटरी दुकानदारो के रोजगार के लिए चिन्तित है और न ही नगर निगम उन्होने बताया कि हम पटरी दुकानदारो ने मध्य क्षेत्र के विधायक बृजेश पाठक से भी मुलाकात की लेकिन फिर भी उनकी दुकाने अभी तक नही लगने दी जा रही है। उन्होने बताया कि अमीनाबाद के दुकानदारो ने अमीनाबाद क्षेत्र को नो वेडिंग जोन नगर निगम के द्वारा घोषित करा दिया था जिसके बाद पटरी दुकानदारो ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई थी तब उनकी कोशिश से नो वेडिंग जोन के आदेश को समाप्त कर दिया गया था उनका कहना है कि कोरोना काल मे तीन महीने तक तो सभी कारोबार बन्द रहे लेकिन तीन महीने बाद धीरे धीरे देश अनलाक हुआ और अब लगभग सभी कारोबार शुरू हो गए है बावजूद इसके 178 दिन बीत जाने के बाद भी अमीनाबाद के करीब 1 हजार पटरी दुकानदारो की छोटी छोटी दुकाने नही खुलने दी गई इन पटरी दुकानो से जुड़े करीब 1 हजार परिवार अब भुखमरी की कगार तक पहुॅच गए है उन्होने कहा कि अमीनाबाद के पटरी दुकानदार अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए और अपने रोजगार को चलाने के लिए संघर्ष करते रहेगे उन्होने कहा कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते है कि गरीब पटरी दुकानदारो की आर्थिक स्थिति पर तरस खाते हुए दुकाने खोलने का आदेश दे ताकि उनके कारोबार शुरू हो और करीब 6 महीने से चल रहे कारोबारी संकट से उन्हे निजात मिल सके।

मनरेगा योजना के तहत 22.51 करोड़ मानव दिवस हो चुके सृजित

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत अब तक करीब 6295.96 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 22.51 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 77.95 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है एवं 29479 परिवारों को पूर्ण 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ग्राम्य विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में 26 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य अनुमोदित किया गया था, लेकिन प्रदेश की मानव दिवस सृजन में प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने प्रदेश का अनुमोदित श्रम बजट 35 करोड़ मानव दिवस कर दिया है। उल्लेखनीय है कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन अवधि के दौरान लाखों की संख्या में प्रदेश में वापस आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अप्रैल 2020 से अब तक 94.15 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, जिनमें 11.44 लाख प्रवासी श्रमिक हैं। श्रमिकों को 4515.32 करोड़ रूपये मजदूरी का भुगतान करके तालाबों, नदियों का पुनरोद्धार, चेकडैम, कूपों, मार्गों आदि के 5.36 लाख कार्य शुरू कराये गये हैं। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चयनित 31 जनपदों में 5.83 करोड़ मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं तथा करीब 1767 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय एवं 176589 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

पॉच वर्षीय संविदा प्रस्ताव पर भड़के कर्मचारी शिक्षक, अगले माह विधानसभा घेराव

कर्मचारी शिक्षक अधिकार एवं पेंशनर्स समाज का उत्पीडन कर रही सरकार

लखनऊ, संवाददाता। कर्मचारी शिक्षक अधिकार एवं पेंशनर्स अधिकार मंच ने सरकारी नौकरी की शुरुआत में पांच वर्ष की संविदा के प्रस्ताव पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि सरकार निरन्तर ऐसे कदम उठा रही है जिससे कर्मचारी- शिक्षक वर्ग को आर्थिक तथा मानसिक पीड़ा का समाना करना पड़ रहा है। कर्मचारी शिक्षक समाज को नकारा घोषित कर सरकार कर्मचारी शिक्षक संवर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा से भी खिलवाड़ कर रही है। ऊर्जा सहित कई विभागों को निजी करण की ओर ले जाने के लिए सरकार इस तरह के दमनात्मक कदम उठा रही है। मंच ने सरकार के सामने पॉच सवाल भी रखे है। इस सम्बंध में मंच की वीडियों कान्फेसिंग में भड़क कर्मचारी शिक्षक नेताओं ने सरकार के इन मनमाने रवैये के खिलाफ अक्टूबर में विधानसभा घेराव से लेकर प्रान्त व्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया है। विडियों कांफेसिंग के दौरान सुशील त्रिपाठी, इं.हरिकिशोर तिवारी,डा.दिनेशचन्द्र शर्मा, यादवेन्द्र मिश्रा,सतीश कुमार पाण्डेय ने महत्वपूर्ण सुझाव रखें। मंच के नेताओं ने कहा कि सरकारी नौकरी की शुरुआत में पांच वर्ष की संविदा के प्रस्ताव बेरोजगारों में डर और उत्पीड़न जैसे प्रभाव रोजगार मिलने से पहले उत्पन्न हो गए है। सरकार के इस प्रस्ताव को युवा और कर्मचारी विरोधी करार देते हुए मंच के नेताओं ने सरकार को 2022 के चुनाव याद दिलाया है। उनका दो टूक कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि समूह 'ख' व 'ग' की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। परीक्षा के जरिये चुने गए अभ्यर्थी पांच वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से जब बच पाएंगे, तभी पक्की नौकरी मिल पाएगी। संविदा काल में कर्मचारी पूरी तरह बंधुआ बनकर रहेगा। जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है। वर्षो सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते। यही नही उनका आरोप यहॉ तक है वर्तमान समय में ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे 90 प्रतिशत ठेका कार्मिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय से 20 से 30 प्रतिशत की कटौती कर ठेकेदार भुगतान कर रहा है। बैठक में कहा गया कि निजीकरण, वेतन,भत्तों मे कटौती, पुरानी पेंशन बहाली,आउटसोर्सिंग, संविदा बंद कर नियमित नियुक्तिउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोनाकाल महामारी के दरमियान ही कर्मचारियों के शोषण करने का एक नया तरीका निकाल लिया है। कर्मचारी की भर्ती के बाद 05 वर्ष तक हर 06 महीने में समीक्षा की जाएगी। बैठक में कहा गया कि जो कर्मचारी नियुक्त होगा उसको 05 वर्ष तक मानदेय आउसोर्सिंग निर्धारित वेतन मिलेगा वह कर्मचारी काम करेगा। जो कर्मचारी नया नियुक्त होगा वह एकाउंटिंग से लेकर मॉनिटरिंग का काम भी देखेगा ऐसे में वह अधिकारियों के दबाव में रहेंगा और उन नियमों का पालन किसी कीमत पर अधिकारियों से नहीं करा पाएगा। क्योंकि अधिकारी जैसा चाहे वैसा उनको लिखना अथवा प्रस्तुत करना उनकी मजबूरी होगी। क्योंकि हर 06 महीने में नौकरी से निकाला जाएगा। सरकारी कर्मचारी के प्रत्येक पद की कार्मिक नियमावली है।

सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा मोदी का जन्मदिन

लखनऊ, संवाददाता। यूपी में भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पीएम मोदी का जन्मदिन 17 को सितंबर है। उसके उपलक्ष्य में कार्यकर्ता 14 सितंबर से 20 सितंबर तक यानी पूरे सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए मंगलवार को प्रदेश भर में चश्मा वितरण का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सेवा सप्ताह के अवसर पर चश्मा वितरण किया। पुरनिया स्थित विधायक नीरज बोरा के कार्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को चश्मे वितरित किये। इस अवसर पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी की मानें तो पीएम मोदी भारत के नवनिर्माता यानी भारत के विश्वकर्मा हैं। पूरे सात दिन तक पार्टी अलग-अलग विषयों पर पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित करेगी।

अंदरूनी आकलन में लखनऊ क्षेत्र की दोनों एमएलसी सीटें जीत रही है भाजपा

डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा के साथ 53 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं की बैठक

लखनऊ, संवाददाता। आने वाले एमएलसी चुनावों में लखनऊ खंड क्षेत्र के लिए भाजपा आश्वस्त नजर आ रही दिखती है. पार्टी के राजधानी दफ्तर में सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा की अगुवाई में दोनों एमएलसी सीटों के लिए पिछले दो दिनों से जारी मनन-मंथन का कुछ यही लब्बो-लुआब रहा,गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्नातक-एमएलसी सीट के लिए लखनऊ खंड क्षेत्र से युवा नेता इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह पर भरोसा जताया है, वहीं शिक्षक-एमएलसी सीट के लिए उमेश द्विवेदी को टिकट दिया गया है। चुनावी तैयारियों को और तेज करने, साथ ही जमीनी हकीकत आंकने के लिए, लखनऊ दफ्तर पर 7 जिलों के 53 विधानसभा क्षेत्रों के आला नेताओं का दो दिन लगातार चिंतन-मनन चला. लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ से जुटे प्रभारियों, संयोजकों, समन्वयकों और दूसरे नेताओं की रायशुमारी में यह निकल कर आया कि भाजपा विरोधी दलों और दूसरे नेताओं से मीलों आगे है, जरूरत यह है कि इस बढ़त को बनाये रखा जाये. माना गया कि दूसरे प्रत्याशियों से बेहतर दावेदारों की वजह से जीत भाजपा के पाले में आती दिख रही है,मसलन, स्नातक क्षेत्र एमएलसी सीट के लिए पार्टी ने जिस प्रत्याशी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, को मैदान में उतारा है वो अपनी साफ-सुथरी छवि, जमीनी जुड़ाव और सौम्य छवि के चलते पहले से ही लोकप्रिय रहे हैं. कहा जा रहा है कि निजी छवि, भाजपा का ताकतवर संगठन और पार्टी के अपने वोट बैंक लखनऊ क्षेत्र की स्नातक-एमएलसी सीट पक्की कर रहे हैं,उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तो स्वीकार किया, ÷अवनीश सिंह शिक्षकों, छात्रों और कॉलेजों के मसलों पर मुझसे लगातार चर्चा करते हैं, नई शिक्षा नीति के स्वरूप पर भी इनके फीड-बैक से मदद मिली÷. शिक्षक-एमएलसी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है. भाजपा प्रत्याशी की शिक्षकों पर व्यापक पकड़ इस सीट पर भी भाजपा के लिए उम्मीद बन रही है,गौरतलब है कि प्रदेश में विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आठ-आठ विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं. इन 16 एमएलसी में 11 का कार्यकाल 6 मई 2020 को पूरा हो रहा है. इनमें पांच एमएलसी स्नातक क्षेत्र के हैं और 6 शिक्षक क्षेत्र के.है।

तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने सुनी जनता की फरियाद

➲ समस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया: जिलाधिकारी

बस्ती। समस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस के समापन अवसर पर उन्होने कहा कि बेहतर निर्णय होने पर आम जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास बढता है। उन्होने निर्देश दिया कि आज प्राप्त सभी 99 प्रकरण में अधिकारी-कर्मचारी मौके पर जाकर शिकायतकर्ता को सुनकर समस्या का निस्तारण करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होंगी।

उन्होने कहा कि कोविड-19 से हमारी जंग जारी है। हमें आमजनता के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को भी सुरक्षित रखना है। कार्यालय में कोविड-19 का सभी प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाय। सभी कर्मचारी शारीरिक दूरी बनाये रखते हुए मास्क का प्रयोग करें। हाथो को नियमित रूप से धोते रहे। साथ ही कार्यालय में आने वाले लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।

लगभग 06 माह बाद आयोजित हो रहे तहसील दिवस का स्वरूप काफी बदला हुआ था। तहसील दिवस का आयोजन तहसील सदर के प्रांगण में घने नीम के छाव के नीचे किया गया था। सभी अधिकारियों एवं

शिकायतकर्ताओ के दूर-दूर कुर्सी लगाकर बैठने की व्यवस्था की गयी थी। मुख्य द्वार पर प्रत्येक आने वाले का विवरण नोट किया जा रहा था इसके बाद थोड़ी दूर पर शिकायत के पंजीकरण की व्यवस्था की गयी थी। शिकायत का पंजीकरण करने के पश्चात शिकायतकर्ता को एक टोके दिया जा रहा था जो मंच पर अधिकारियों के सामने सुनवाई के समय प्रस्तुत करना होता था। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, सीएमओ डॉ0 एके गुप्ता, एसडीएम सदर आशाराम वर्मा, जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव ने शिकायतों की सुनवाई कर उनके निस्तारण का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण माह के अन्तर्गत 06 गर्भवती तथा 07 किशोरी बालिकाओं के साथ 04 अतिकुपोषित बच्चों के परिवार को पौष्टिक आहारयुक्त पोषण डलिया भेट किया। साथ ही एक सहजन का पौधा भी दिया, जिसे वे अपने घर से आस-पास रोपित करेंगे। इस अवसर पर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मिथिलेश बौद्ध के निर्देशन में सदर, सॉउघाट शहर, बनकटी, कुदरहॉ तथा बहादुरपुर बाल विकास परियोजना के अधिकारियो ने पोषक अभियान के अन्तर्गत पौष्टिक आहार तथा स्वच्छता संबंधी स्टाल प्रदर्शित किया। इस अवसर पर उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह, डॉ0 बृजभूषण मौर्या, अधिशासी अभियन्ता विद्युत संतोष कुमार तथा अमित कुमार, डॉ0 अश्वनी तिवारी, रमन मिश्र, विनय सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अखिलेश त्रिपाठी, विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मैसेंजर ऑफ पीस स्काउटिंग का अभिन्न अंग-अमर क्षेत्री

बस्ती। नेशनल एडवेंचर यूथ कॉम्प्लेक्स गदपुरी में चल रहे नेशनल एडवेंचर कम कोविड-19 अवेयरनेस कैम्प में सहायक निदेशक भारत स्काउट और गाइड नई दिल्ली अमर क्षेत्री ने प्रतिभागियों द्वारा मैसेंजर ऑफ पीस का चिन्ह बनवाकर विश्व शांति का संदेश दिया,कहा कि मैसेंजर ऑफ पीस के मेम्बर नित नये समाजहित में अपना योगदान देते रहते हैं, हमें इन शान्ति के दूतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता हैं, सामान्य हालात से लेकर विषम आपदाओं में भी यह अपने दायित्वों से विरत नही होते हैं।

उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे मैसेंजर ऑफ पीस कोऑर्डिनेटर कुलदीप सिंह,मैसेंजर ऑफ पीस कोऑर्डिनेटर गौरव शुक्ल,मैसेंजर ऑफ पीस कोऑर्डिनेटर अभिलाशा मिश्रा ने इसमें योगदान दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहन्ती,लीडर ऑफ द कोर्स यशपाल हुड्डा,डॉ.योगेश कुमार टोंक,मोहिन्दर सिंह,धनराज,जीत घोष,विलकिश शेख,करन चढ्ढा,गौरव शुक्ल,अभिलाषा मिश्रा,जाकिर हुसैन, रितेशनी मिश्रा,मंजूला सिंह, विशाल कुमार सरोजबाला,कन्हैया,यूसुफ, मच्छेन्द्र नाथ आदि की सहभागिता रही।

नवागत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

संत कबीर नगर। नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में नव निर्मित खलीलाबाद तहसील सभागार में कोविड-19/कोरोनो संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन करते हुये सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने एक-एक फरियादी/शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत तौर पर रूबरू होते हुये उनकी शिकायत सुनी तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को अविलम्ब एवं गुणवत्तायुक्त समाधान कराने का भी निर्देश भी दिया। उन्होंने प्राप्त सभी शिकायतों एवं लम्बित प्रकरणों का समय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश देते हुये कहा कि अधिकारीगण आवश्यकतानुसार स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करें तथा शिकायतकर्ता को सुनकर आपसी सुलह समझौतों से विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक भू-सम्पत्तियों चकमार्गों आदि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। शिकायती मामलों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करा दिया जाये तथा अधिक समय से लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के कारणों का भी उल्लेख किया जाये। समाधान दिवस में मिले संदर्भों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच के लिये औचक रूप से शिकायतकर्ताओं से उनके मोबाइल नम्बर पर बात भी की जाये। आज आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 मामले प्रस्तुत किये गये, जिसमें 04 मामलों का मौके पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रयास से मौके पर तत्काल निस्तारण करा दिया गया।

हरैया पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

बस्ती। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष हरैया सर्वेश राय के कुशल नेतृत्व में थाना हरैया पुलिस द्वारा मंगलवार को मुरादीपुर चौराहा के पास से अभियुक्त 1.लालबाबू पुत्र राम अवतार सा0 थान्हाखास थाना हरैया जनपद बस्ती 2.रणजीत यादव पुत्र स्व0 आज्ञाराम यादव सा0 थान्हाखास थाना हरैया जनपद बस्ती के पास से दो प्लास्टिक के गैलन में 20-20 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना हरैया पर मु0अ0सं0 235,236/2020 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए जन अभियान चलाएगी कांग्रेस

- हर सदस्य की जिम्मेदारी तय, जनता की राय से बनेगा घोषणा पत्र
- महासचिव प्रियंका गांधी ने की मैनिफेस्टो कमेटी के साथ बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कीं। बैठक में चुनावी घोषणा पत्र बनाने को लेकर मजबूत रणनीति तैयार हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिगड़ते आर्थिक हालात पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि पूरे प्रदेश में जनअभियान चलाकर कॉंग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाएगी। इस अभियान में विधानसभावार बैठकें करके जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई मीटिंग में तय हुआ कि सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये भी जनता से रायशुमारी की जाएगी। प्रदेश भर के बौद्धिक वर्ग और जन संगठनों से लिखित रूप से भी सलाह मांगी जाएगी। चुनावी घोषणा पत्र के लिए विधानसभा वार आम लोगों से भी इस तरह के सुझाव और मुद्दे आमंत्रित किये जायेंगे। बैठक में मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्य सलमान खुर्शीद, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, सुप्रिया श्रीनेत्र, विवेक बंसल, अमिताभ दुबे के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल नेता आराधना मिश्रा मोना उपस्थित थीं।

योगी सरकार 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को जबरन करेगी रिटायर

महराजगंज। महराजगंज में बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार सख्त तेवर अपना चुकी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्ट पुलिसवालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नाकारा पुलिसवालों की सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने निर्देश दिए गए है. वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के लिए स्क्रीनिंग. उधर, योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में भृष्ट पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है. उन पुलिसवालों की छंटनी की जाएगी, जो 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है. अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी. मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है. ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया था।

कुपोषण मिटाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा गाय का दूध

मुसहर समुदाय के दो अति कुपोषित बच्चों के परिवार को डीएम ने सौंपी गाय

गाय के दूध से फायदे

- बच्चों के बौद्धिक विकास में लाभदायक है।
- बच्चों की पाचन शक्ति मजबूत होती है।
- बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
- बच्चों को सूखा रोग से भी बचाता है
- बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाता है।
- विभिन्न बीमारियों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है।
- बच्चों को संपूर्ण पोषक तत्व मिलता है।
- बच्चों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिलता है।

महराजगंज। सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह से तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने मुसहर समुदाय के दो अति कुपोषित बच्चों के परिवार वालों को सोमवार को एक-एक गाय सौंपा। उन्होंने कहा कि गाय के दूध से जहाँ बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वहीं कुपोषण से मुक्ति भी मिलती है। मधवलिया गोसदन से डीएम ने ग्राम पंचायत बड़हरा चरगहा के स्थान टोला निवासी मुसहर समुदाय के 14 माह की रागिनी तथा 15 माह के आदित्य (दोनों अतिकुपोषित) बच्चों के परिवार को गाय सौंपते हुए कहा कि कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पहले से भी पोषाहार सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजना का लाभ लाभार्थियों को मिलता रहता है। मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि इस साल मनाए जा रहे तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह में अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गाय भी उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं गौसेवा के लिए नौ सौ रूपये भी देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पोषण माह के तहत जहां सभी 3133 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित अतिकुपोषित बच्चों का वजन तथा लंबाई का माप लेकर चिन्हित किया जा रहा है, वहीं किचन गार्डेन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेन्द्र कुमार राय ने कहा कि जिले में नए सिरे से कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि सभी को कुपोषण से मुक्त करने की व्यवस्था बनायी जा सके। उन्होंने कहा कि इस माह हो रहे चिन्हीकरण कार्यक्रम में जो बच्चे अति कुपोषित पाए जा रहे हैं उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भेजा जा रहा है ताकि वहां उचित देखभाल करके कुपोषण से मुक्त किया जा सके। बाल विकास परियोजना अधिकारी निचलौल मनोज कुमार शुक्ला ने कहा कि पोषण माह के तहत बच्चों, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं में पोषाहार से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर सेवन करने की भी सलाह दी जा रही है। निचलौल क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू देवी ने अपने क्षेत्र के जिन अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया उन दोनों को गाय उपलब्ध कराई गयी है। इसी प्रकार अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करें। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीएम, सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों ने मधवलियां गोसदन में पौधरोपण भी किया।

पिता ने लगाई पुलिस से न्याय की गुहार

महाराजगंज। नौतनवां थाना क्षेत्र के सोनपिपरी गांव निवासी एक परिवार वर्ष भर से अपने घर के एक 23 वर्षीय युवक के हत्या मामले में न्याय के लिए दर-दर भटकने को विवश है। आरोप है कि पुलिस ने उनके आरोपों को दरकिनार कर हत्यारोपियों को

खुला छूट दे दी है अब वही कथित हत्यारे फिर जान माल की धमकी दे रहे हैं। बताया गया कि बिगत 16 मई 2019 को एक युवक का शव पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के गजपति गांव के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था और उसका सर धड़ से अलग था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर व सिर में कई स्थानों पर चोट लगने की पुष्टि हुआ था। जिससे मामला संदिग्ध बना दिया था। मृत युवक की पहचान 23 वर्षीय चुन्नीलाल पुत्र राधेश्याम निवासी सोनपिपरी टोला सिंह थाना क्षेत्र नौतनवा के रूप में हुई थी। युवक की दीदी सावित्री गजपति गांव में रहती थी।

हर दिन बदल जाएगा मरीजों के बेड सीट का रंग, आदेश बनी मुसीबत

इमरजेंसी ओपीडी ड्यूटी का चार्ट जारी, ड्यूटी न करने वालों की आई शामत

अयोध्या। अपर निदेशक और जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के फरमान ने चिकित्सा कर्मियों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है।अब हर दिन अलग-अलग रंग की चादर मरीजों के पेट पर बिछाई जाएगी। यही नहीं इमरजेंसी ओपीडी ड्यूटी की जो नई सूची जारी हुई है उसमें उन फार्मासिस्ट की मुसीबत बढ़ गई है जो इमरजेंसी ड्यूटी से कराया करते थे, नए फरमान के अनुसार अब उन्हें भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। फार्मासिस्ट व्यास सिंह और बीके श्रीवास्तव ऐसे 2 कर्मचारी हैं जिन्होंने कभी इमरजेंसी ओपीडी ड्यूटी किया ही नहीं है।

सरकारी अस्पताल की नई व्यवस्था के तहत मरीजों के बेड की चादर रविवार को नारंगी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नीला और शनिवार को नारंगी रंग की होगी। इस व्यवस्था में भी घोटाले की बू आ रही है, रंग बिरंगी चादर खरीदने में लंबा हेरफेर किया जाना संभावित है। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है।

बताते चलें कि इसके पहले सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बेड की चादर सफेद रंग की हुआ करती थी, जाड़े के महीनों में जो ऊनी कंबल मरीजों को दिया जाता था उसका रंग लाल होता था! चादरों की खरीद की फौज में जांच कराई जाए तो इसमें भी घोटाला का जिन्न बाहर आ निकलेगा।

चिलुआताल थाने का कप्तान ने किया औचक निरीक्षण

गोरखपुर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार अचानक चिलुआताल थाने पर आज सुबह मंगलवार को लगभग साढे इग्यारह बजे दिन में जिले के कप्तान जोगीन्दर सिंह अचानक चिलुआताल थाने पर पहुंच कर थाने के निरीक्षण के साथ ही एक एक बिन्दु पर जाँच करते हुये नजर आए। कार्य प्रणाली मे सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। एसएसपी ने थाने पर पहुंचते ही थाना परिसर का निरीक्षण किया हालाकि उस वक्त बूदा बादी होने के कारण निरीक्षण एक औपचारिकता ही रही फिर शुरू हुआ एक एक बिन्दु पर गहनता से जाँच पड़ताल किये कार्यालय में अभिलेखो के रख रखाव का निरीक्षण किया गया। मुख्य रूप से अपराध और अपराधियो पर अंकुश एवं लम्बित विवेचनाओ का अभिलम्ब निस्तारण के लिये जोर दिया गया। एसएसपी थाना परिसर में लगभग एक घंटे तक रहकर निरीक्षण का कार्य पूर्ण करने के बाद मुख्यालय की तरफ रवाना हो गये।

मुख्यमंत्री द्वारा वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यो की मण्डलीय समीक्षा बैठक

➲ विकास कार्यो/कल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि की कोई कमी नही होगी। ➲ जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण तथा सम्बंधित संस्थाएं आपसी तालमेल एवं समन्वयता के साथ गुणवत्ता युक्त एवं मानक के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। ➲ परियोजनाओं और विकास कार्यो में गुणवत्ता एवं मानक के साथ-साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। ➲ जनपद संत कबीर नगर के मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना एवं हैरिटेज सर्किट स्वदेश दर्शन मगहर के निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश ➲ निर्माणाधीन मार्गो के चैडीकरण एवं सुदृढ़कीरण का कार्य गुणवत्तायुक्त ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश ➲ राजस्व संग्रह की विभागवार पाक्षिक समीक्षा करने के निर्देश। ➲ जनपद संत कबीर नगर को राजकीय इण्टर कॉलेज देने का आश्वासन

संत कबीर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियों काफ्रेसिंग के माध्यम से जनपद में रू0 10 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य लागत की परियोजनाओं/निर्माण कार्यो सहित जनपद में संचालित लाभार्थीपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में प्रगति, किसानों हेतु खाद, बीज एवं पानी की उपलब्धता सहित कोविड-19/कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु किये जा रहें कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गयी। वीडियों काफेसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के राज्यमंत्री श्रीराम चैहान, विधायकगण दिग्विजय नारायण जय चौबे, एवं राकेश सिंह बघेल से निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में बिन्दुवार फीड बैक प्राप्त किया उनके विधानसभाओं के चैमुखी विकास में शिक्षा, सड़क, स्वच्छ पेयजल, अस्पताल, आदि की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया एवं शासन स्तर से उसे पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को जनपद में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। जनपद के विकास की गति में तेजी लाने का निर्देश देते हुए परियोजनाओं और विकास कार्यो को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानक के अनुसार पूर्ण कराने जाने का निर्देश दिया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी परियोजना/निर्माण कार्य के निर्धारित अवधि में पूर्ण होने पर लागत में कमी आने के साथ-साथ जनसामान्य को विकास योजनाओं का ससमय लाभ मिलता है तथा शासन एवं प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने निर्धारित समीक्षा बिन्दुओं/विकास कार्यो के प्रगति की अद्यतन स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत किया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, निर्माण, लाभार्थीपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन एवं जनसामान्य के बहुआयामी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए शासन स्तर से धनराशि की कोई कमी नही आने दी जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता पाये जाने पर सम्बंधित की जबावदेही सुनिश्चित करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें कोरोना सक्रमण से बचाव करते हुए, पूरी सतर्कता एवं सावधानी अपनाते हुए विकास कार्यो को तीव्र गति से सम्पन्न कराने हेतु पूरे मनयोग से कार्यो/कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता के साथ लगे रहना है। उन्होंने कोविड-19/कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराये जाने के भी निर्देश दिये। ''दो गज की दूरी-मास्क है जरूरी'' के साथ-साथ सेनेटाइजर एवं साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। कोविड कन्ट्रोल सेन्टर के साथ-साथ एल-1/एल-2 अस्पताल को निरंतर सक्रिया रखा जाए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास कार्यो/परियोजनाओं में निरंतरता एवं प्रगति के आधार पर आवश्यकतानुसार मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक समीक्षा की जाए, जिससे उन्हें मानक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो की भौतिक प्रगति से अवगत कराते हुए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा जाए। जिससे शासन स्तर पर भी धनराशि स्वीकृति करने से सम्बंधित कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता से जुड़े प्रकरणों में तत्काल निर्णय लेते हुए समाधान निकाला जाए। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लम्बित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया जाए। जनपद के विकास कार्यो में जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायत सचिवालय एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण सम्बंधी कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिये गये। ग्राम पंचायत सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किये जाने के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने सम्बंधित विधायकों एवं जिलाधिकारी से निर्माण कार्यो में प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्माण कार्यो में तेजी लाते हुए पूर्ण कराने के निर्देश दिये। जानकारी दी गयी कि जनपद के मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना हेतु 23.59 करोड़ की स्वीकृत लागत के सापेक्ष 13 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

गांव को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी

आज जब पूरी दुनिया कोरोना के विपरीत प्रभावों से जूझ रही है, तब हमारा देश इस संकट से सफलतापूर्वक निपट रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल कोरोना पर नियंत्रण के लिए तकनीकी साधनों और परीक्षण व उपचार की व्यवस्थागत तैयारियों को अंजाम दिया, बल्कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के गांवों पर यकीन दिखाया. प्रधानमंत्री ने कोरोना की आरंभिक अवधि में ही कहा था कि कोरोना संकट ने हमें आत्मनिर्भर बनने का एक रास्ता दिखाया है. महात्मा गांधी ने अपने ग्राम स्वराज में गांव के विकास का जो खाका खींचा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में आत्मनिर्भरता की जो तस्वीर थी, उसका मर्म हमें प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत में दिखायी देता है. ऐसा भारत, जहां गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बने. गांव से तहसील, तहसील से जिला और फिर राज्य व देश आत्मनिर्भर बनें. एक मनीषी का कथन है कि अपने संकटों का हल हमें अपने अतीत, अपने विद्वानों के कहन और ग्रंथों में बसे ज्ञान में खोजना चाहिए. अपनी पुस्तक 'भारतीय अर्थनीति- विकास की एक दिशा' में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए पं. उपाध्याय कहते हैं कि हमारा आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है. यदि हमारे यहां आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी सहायता पर निर्भर रही, तो वह अवश्य ही हमारे ऊपर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बंधनकारक होगी. इस महामारी में, जब देश में सभी आर्थिक गतिविधियां लगभग दो महीने बंद रही, तब उन्हें खड़ा करने के लिए केवल आर्थिक प्रोत्साहन देना ही काफी नहीं था, बल्कि कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर वस्तुओं के विक्रय और उनके उत्पादन शृंखला की प्रत्येक कड़ी तक परिश्रम का उचित मूल्य पहुंच जाना आवश्यक था. विकास का संतुलित मार्ग भी यही है कि हर पायदान पर मौजूद व्यक्ति को उसका वाजिब हक मिले. गांवों की अर्थव्यवस्था को शक्ति देने के लिए तय किया गया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष ग्रामीण भारत के विकास एवं ग्रामीणों के कल्याण पर लगभग दो लाख करोड़ रुपया व्यय करेगा. इसमें से अब तक एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की जा चुकी है. लॉकडाउन के बीच अपने रोजगार से हाथ धो बैठे मजूदर जब गांव पहुंचे, तब उनके सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ. ऐसे में इन श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान आरंभ किया. इसके तहत छह राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को काम दिया गया. इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया था. गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कुल 25 करोड़ 75 लाख 68 हजार 175 श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया. इसमें कुल 21 हजार 549.32 करोड़ रुपये व्यय हुए. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और अर्थ तंत्र की सुदृढ़ता के लिए मनरेगा को माध्यम बनाया गया. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 192.97 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार का सृजन, 9.93 करोड़ लोगों को जॉब ऑफर देना और राज्यों को 58,960.52 करोड़ की राशि जारी की गयी है. इतना ही नहीं, 1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा की मजदूरी दर औसतन 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गयी है. मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. मनरेगा आवंटन 61,650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,01,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. गांवों के विकास में सबसे बड़ा प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता का होता है. गांवों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान बनी है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के तहत 82 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क निर्मित करने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत देश में अब तक 26000 किलो मीटर सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 2.95 करोड़ आवास निर्मित करने का लक्ष्य है. अब तक 2.21 करोड़ आवास राज्यों को आवंटित किये जा चुके हैं. लगभग एक करोड़ से ज्यादा आवास बन चुके हैं. योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के पास अब तक कुल 1,60,555.29 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है. वर्ष 2022 तक सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प है. कुल 20.65 प्रधानमंत्री महिला जनधन खाताधारकों को तीन माह के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की अनुग्रह राशि प्रदान की गयी. इस योजना पर कुल 31,000 करोड़ रुपये व्यय किये गये. वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों के लिए दो किश्तों में कुल 1000 रुपये की सहायता जारी की गयी. इसके लिए 2,815 करोड़ रुपये खर्च किये गये. 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांग इससे लाभान्वित हुए. मिशन अंत्योदय की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 76 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में आंतरिक सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. अभी तक लगभग 1.40 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं. ग्रामीण विकास की इस अवधारणा में पंचायती राज मंत्रालय की महती भूमिका है. देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था को सशक्त करने, गांव तक सुराज पहुंचाने और शासन व्यवस्था की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली लागू की गयी है. भारत में 2 लाख 69 हजार 347 ग्राम पंचायतें, 6 हजार 717 ब्लॉक पंचायत तथा 654 जिला पंचायतें हैं. पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पंचायती राज के सभी स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 60,750 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिसमें 50 प्रतिशत अबद्ध (अनटाइड) और 50 प्रतिशत बद्ध (टाइड) हैं।

अबद्ध एवं बद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में 30,375 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं.प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की सफलतम अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना देखा है, वह गांवों के विकास के बगैर संभव नहीं है. हम अपनी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत के बीच पैदा हुई विकास की खाई को अपने ही संसाधनों से पाटने में सफल हो रहे हैं।

सम्पादकीय

जिनपिंग का बिखरता सपना

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दशक भर से चर्चा है कि दुनिया में राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है. शक्ति पश्चिमी दुनिया से खिसककर एशिया की ओर मुड़ रही है, जिसका सबसे प्रबल दावेदार चीन है. चीन की आर्थिक और सैनिक व्यवस्था में पिछले चार दशकों में बहुत बदलाव हुआ है. उसे उम्मीद है कि 2035 तक वह सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जायेगा और शक्ति में भी वह पहले पायदान पर पहुंच जायेगा. लेकिन, ऐसा होता हुआ दिखायी नहीं देता. प्रो रिचर्ड हास का मानना है कि महाशक्ति बनने के लिए कई गुणों की जरूरत पड़ती है. जिनमें दो गुण विशेष हैं- पहला, दुनिया के किसी भी हिस्से में सैनिक हस्तक्षेप तथा दूसरा, कहीं भी आण्विक प्रक्षेपास्त्र दागने की क्षमता. ये दोनों क्षमता आज यदि किसी देश के पास है, तो निश्चित रूप से वह अमेरिका ही है. दोनों ही मानकों पर चीन की मठाधीशी कारगर नहीं दिखती. चीन एशिया का निष्कंटक संप्रभु बनने की कोशिश में है. भारत के साथ उसका सीमा विवाद इसी का नतीजा है. लेकिन, भारत ने उसे चुनौती दी है. जब चीन और भारत एक साथ राजनीतिक छवनी बनाने की तैयारी में जुटे थे, तो अमरीका ने भारत को अपना हितैषी माना था. 13 सितंबर, 1949 के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आलेख छपा था कि भारत चीन की शक्ति को रोकने में कामयाब होगा. भारत 65 वर्षों तक चीन की आत्मीयता के लिए सबकुछ त्याग करता गया. सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता और तिब्बत का त्याग जैसे उदाहरण दुनिया के सामने हैं. फिर भी चीन भारत के साथ छल करता रहा. हिमालय के सीमावर्ती देशों में अपनी धाक जमाने के साथ, वहां भारत विरोध की लहर पैदा करना चीन के छल का हिस्सा बन गया. हम एक चीन के सिद्धांत को शिद्दत के साथ मानते रहे, लेकिन चीन लचर और लाचार पड़ोसी के रूप में हमारे प्रति अपनी धारणा बनाता गया. बदलाव का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से शुरू की और फिर वह नेपाल गये. यह एक गंभीर संदेश था चीन के लिए. हिमालयी देश भारत की विशेष मैत्री और संप्रभुता के अंग हैं.

शीत युद्ध के कोलाहल ने भारत को दोयम दर्जे के देश के रूप में रूपांतरित कर दिया था. भारतीय विदेश नीति पूरी तरह से पाकिस्तान उन्मुख बन चुकी थी, जिसे बनाने वाले प्रधानमंत्री नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री मेनन थे. वर्ष 1962 के युद्ध के पहले जब सेना प्रमुख चीनी आक्रमण के लिए चिंतित थे, तो रक्षा मंत्री पाकिस्तान के साथ युद्ध पर आमादा थे. उन्होंने आगरा में यह बात युद्ध के पहले कही थी. अगर 2014 के पहले के भारत के अस्त्र-शस्त्र का आकलन करेंगे, तो भारत की सुरक्षा नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाती है. भारत के पास चीन के विरुद्ध लड़ने की कोई तैयारी ही नहीं थी. डोकलाम के बाद सरकार प्रयासरत हुई. उसके बाद ही चतुर्भुज आयाम बना, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. एशिया-पैसिफिक को इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) के रूप में रूपांतरित कर दिया गया. पूर्वी एशिया में चीन की धार को कुंद करने के लिए भारत को विशेष अहमियत दी जाने लगी. चीन के पड़ोसी देश भारत के साथ सैनिक अभ्यास में शरीक होने लगे. बदले में चीन ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सैन्य गतिविधि को और मजबूत बनाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की पीठ पर जोंक की तरह चिपक चुका है. उसकी अपनी कोई स्वतंत्र नीति नहीं है. लेकिन चिंता की लकीर नेपाल को लेकर खिंच रही है. भारत नेपाल को चीन का पिछलग्गू देश बनते हुए नहीं देख सकता. फिलहाल चीनी सेना पिछले पांच महीनों से भारतीय सीमा के भीतर घुसने के लिए बेताब है. पिछले दिनों सीमा पर जब चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ायी गयी, तो भारत ने भी अपनी ताकत को बढ़ाकर दुगना कर दिया. यदि भारत ने तिब्बत कार्ड खेलना शुरू कर दिया, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिवास्वप्न पर आघात लग सकता है. पिछले कुछ महीने में चीन के पांच बड़े नेता, जो पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, तिब्बत जा चुके हैं और भारत के साथ संघर्ष के लिए उन्हें तैयार करने की सीख दे रहे हैं. तिब्बत के धर्मगुरु भारत में हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से चलायी जाती है. तिब्बत के लोग अपनी मातृभूमि के लिए संघर्षरत हैं. अगर भारत का उन्हें साथ मिला, तो तिब्बत के जांबाज चीन के सैन्य बल को तोड़ने का काम कर सकते हैं. भारत के लिए भी जरूरी है कि तिब्बत कार्ड का प्रयोग अब किया जाये. यदि चीन सफल हुआ, तो दशकों तक भारत को शुतुरमुर्ग की तरह जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा. अगर चीन की हार हुई, जिसकी संभावना पूरी है, तो विश्व राजनीति में भारत का प्रभाव कई गुना बढ़ जायेगा।

टीवी चैनलों का रिया गिरफ्तारी अभियान

इस समय केवल मुंबई के ही नहीं बल्कि अधिकांश बड़े राष्ट्रीय स्तर के खबरी टीवी चौनलों का अधिकांश समय भारत-चीन सीमा विवाद के बाद अभिनेत्री कंगना शिवसेना विवाद पर चर्चा करने पर जा रहा है। कोरोना संक्रमण से संबंधित समाचार इन चौनलों पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है तथा आईपीएल क्रिकेट मैच स्पर्धा तो समाचारों में पहले 10 स्थानों पर भी नहीं है। कंगना शिवसेना विवाद की शुरूआत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समाचार के बाद प्रारंभ हुई। टीवी चौनल रिपब्लिक इंडिया और इसके हिन्दी संस्करण रिपब्लिक भारत का दावा है कि उसने ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या करार देते हुए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया था जो नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद पूरा हुआ। रिपब्लिक टीवी का दावा है कि उसकी रिया की गिरफ्तारी के मुहिम के समाचारों की दर्शकों में लोकप्रियता के कारण उसने 22 अगस्त से 28 अगस्त तक की बार्क रेटिंग में इंडिया टुडे और इसके हिन्दी संस्करण आज तक को पछाड़ दिया। रिपब्लिक भारत की अगुवाई में सोशल मीडिया द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित हत्या के आरोप में उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके कड़ी से कड़ी सजा की मांग के अभियान से ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच और फैसला देने वाले न्यायालय की जरूरत ही नहीं थी। सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती को सीधे जेलखाने भेज देना चाहिए था। रिया चक्रवर्ती का साक्षात्कार दिखाने वाले इंडिया टीवी और उसके हिन्दी संस्करण आज तक को सोशल मीडिया ने भारी-भरकम धनराशि लेकर साक्षात्कार ठहराते हुए उसे ट्रोल कर दिया। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को ट्विटर पर बेजरूरी बताने वाले और विरोध करने वालों में अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, विद्या बालन, सोनम कपूर, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, दीया मिर्जा, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा के नाम उल्लेखनीय हैं। सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने इन फिल्मी हस्तियों का उपहास उड़ाया तो कुछ ने नगरीय नक्सली गैंग की विचारधारा वाले लोग करार देते हुए उन्हें महत्व नहीं देने की सलाह दे डाली। दर्शकों में लोकप्रियता और व्यवसायिक आमदनी की दृष्टि से भारत के बड़े टीवी न्यूज चौनलों में इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, एबीपी, इंडिया टीवी, दूरदर्शन, न्यूज-18, एनडीटीवी तथा टीवी-9 भारत में उल्लेखनीय हैं। सर्वविदित है कि दूरदर्शन सरकारी चौनल है। इन चौनलों में व्यवसायिक आमदनी की दृष्टि से इंडिया टुडे चोटी पर जमा हुआ है। इसका प्रमुख कारण लिविंग मीडिया के इंडिया टुडे समूह को सदैव ही कारपोरेट उद्योग ग्रुप अपने हितों का पोषक समझते रहे हैं। प्रथम पांच चौनलों में से एक भाजपा समर्थक सांसद एस्सेल ग्रुप के सुभाष चन्द्रा का जीटीवी और पत्रकारिता में कदम रखने से पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने वाले रजत शर्मा का इंडिया टीवी अपने आपको भाजपा समर्थक चौनल कहने की बजाय राजनीतिक दलों से परे चौनल मानते हैं। किंतु 2019 से सबसे अधिक लोकप्रिय चौनल होने का दावा करने वाले रिपब्लिक भारत के प्रमुख कर्ताधर्ता अर्णव गोस्वामी ने सोच समझकर रिपब्लिक इंडिया को भाजपा का हाउस चौनल बना दिया है। इन बड़े चौनलों में एनडीटीवी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है जिसका श्रेय दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापन और कलकत्ता की चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म प्राइस वाटर हाउस के कंसल्टेंट के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत करने वाले इसके संस्थापक प्रणव राय को जाता है। एनडीटीवी के हिन्दी संस्करण के संपादक रवीश कुमार हैं जिन्होंने अपनी अलग निरपेक्ष पहचान बना रखी है। रिपब्लिक टीवी तथा बाद में अनेक लोगों ने सोशल मीडिया में दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती की शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से नजदीकियों के कारण मुंबई पुलिस दबाव में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, किंतु आज तक सोशल मीडिया आदित्य ठाकरे की रिया चक्रवर्ती से तनिक सी भी जान-पहचान प्रमाणित करने में असफल रहा है। भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा वाय प्लस श्रेणी की सुरक्षा से लैस अभिनेत्री कंगना रनौत के 9 सितंबर के मुंबई आगमन के पूर्व बीएमसी द्वारा कंगना के कार्यालय भवन के एक हिस्से में तोड़फोड़ की गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रानौत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए जो संदेश जारी किया, उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक आलोचकों द्वारा भी तू-तड़ाक के धमकी भरे शब्द कभी सुनने को नहीं मिले होंगे। ऐसा लगता है कि कंगना के लिए ये संवाद किसी सिद्धहस्त संवाद लेखक द्वारा लिखे गये थे जिनकी संवाद अदायगी बड़ी कुशलता से अभिनेत्री होने के नाते कंगना ने किया। ऐसा लगता है कि रिपब्लिक टीवी एवं कंगना रनौत एक कॉमन हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दो दिन पहले कंगना रनौत ने बयान दिया कि शिवसेना की छत्रछाया में खान अभिनेताओं एवं निर्माताओं ने मुंबई के फिल्मोद्योग का इस्लामीकरण कर दिया है, यहां रह कर उनका प्रयास फिल्मोद्योग के हिंदुत्वकरण का रहेगा। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित हत्या का संबंध है सीबीआई को समझ में आ गया था कि रिया चक्रवर्ती हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की हत्या नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने रिया को गिरफ्तार करने से परहेज किया। कर प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों को जब लगा कि रिया ने 5 माह तक अपने और परिवार के सारे खर्च सुशांत सिंह राजपूत के खाते से किया करती थीं तो रिया के द्वारा किसी टैक्स चोरी का सवाल नहीं उठता था। इन दोनों के पीछे हटने के बाद हारकर केन्द्र सरकार संभवतरू एनसीबी को इस निर्देश के साथ लाई कि वह ऐन केन प्रकारेण रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करे जिससे बिहार चुनाव में उसको फायदा मिल सके। मेरी समझ में एनसीबी द्वारा रिया की गिरफ्तारी से भाजपा के एजेंडा अनुसार नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जदयू-भाजपा गठबंधन को लाभ मिलना तयशुदा लगता है। लोजपा द्वारा अलग होकर चुनाव लड़ने के बावजूद बिहार में जदयू-भाजपा को जीत मिलेगी। कंगना रनौत के रूप में भाजपा को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसकी इच्छानुसार मुंबई में रहकर उद्धव ठाकरे एवं अन्य शिवसेना नेताओं पर जबानी हमले करके नाक में दम करता रहे। मेरा मानना है कि रिपब्लिक टीवी और कंगना रनौत के शिवसेना पर हर जबानी हमलों की एनसीपी और कांग्रेस पार्टियों पर विपरीत प्रतिक्रिया होगी और उनका शिवसेना को समर्थन और मजबूत होता जाएगा फलस्वरूप उद्धव ठाकरे के पूरे पांच साल मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है।

हिन्दी की इस रात की सुबह कब होगी?

भाषा की गुलामी बाकी तमाम गुलामियों में सबसे बड़ी होती है। दुनिया में जो भी देश परतंत्रता से मुक्त हुए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम अपने सिर से भाषाई गुलामी के गर को उतार फेंकने का किया है। यह काम रूस में लेनिन ने, तुर्की में कमाल पाशा ने, इंडोनेशिया में सुकर्णो ने और एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी-अमेरिकी देशों के दर्जनों छोटे-बड़े देशों ने किया है। लेकिन भारत में जैसा भाषायी पाखंड जारी है, वैसा कहीं और देखने-सुनने में नहीं आता। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक गुलाम रहे देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो अपनी आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी भाषा के स्तर पर किसी भी मौजूदा गुलाम देश से ज्यादा गुलाम है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में फैसले अंग्रेजी में सुनाए जाते हैं, जो आमतौर पर वादियों को समझ में नहीं आते, क्योंकि विदेशी भाषा की तासीर ही कुछ ऐसी है। जबकि इंसाफ का तकाजा यही है कि जो भी फैसला हो वह वादी की समझ में आना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वादियों को उनके वकील ही बताते हैं कि वे मुकदमा हार गए हैं या जीत गए हैं। इस सिलसिले में करीब एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को अदालती कामकाज की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा था। लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देते हुए गेंद को सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही डाल दिया था और याचिका खारिज हो गई थी। सवाल सिर्फ न्यायपालिका के कामकाज का ही नहीं है। तमाम सरकारी और अर्द्ध सरकारी महकमों तथा लोकजीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अंग्रेजी कुंडली मारकर बैठी हुई है। हकीकत यह भी है कि जब कभी हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को उनका हक दिलाने के लिए कहीं कोई आवाज उठती है तो देश का शासक वर्ग यानी नौकरशाह, कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोग, अभिजात्य वर्ग के राजनेता और कुछ बददिमाग अंग्रेजीदां बुद्धिजीवी बुरी तरह परेशान हो उठते हैं। उन्हें अपनी इस लाडली भाषा के वर्चस्व के लिए खतरा दिखाई देने लगता है। अंग्रेजी का अंध हिमायती यह तबका चीख-चीख कर यह साबित करने की कोशिश करने लगता है कि अंग्रेजी ही देश की संपर्क भाषा है और उसके बगैर देश का काम नहीं चल सकता। बेशर्मी के साथ यह बेजा दलील भी दी जाती है कि यदि अंग्रेजी के प्रति नफरत का वातावरण बनाया गया तो यह देश टूट जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पक्षधरों का विरोध अंग्रेजी से नहीं होता है, बल्कि वे तो महज लोकजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी का दबदबा खत्म करने की मांग कर रहे होते हैं। लेकिन अंग्रेजी के बरक्स हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं की बात करने वालों को उसी तरह हिकारत से देखा जाता है जैसे कई यूरोपीय मुल्कों में अश्वेत लोगों को देखा जाता है। यह एक किस्म का भाषायी नस्लभेद है। दरअसल, सवाल सिर्फ हिन्दी का नहीं, बल्कि समूची भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान और सम्मान का है। साथ ही यह संविधान के सम्मान से जुड़ा मसला भी। संविधान की जितनी अनदेखी और अवमानना भारत में होती है, उतनी दुनिया के किसी और देश में नहीं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाया गया और कहा गया कि धीरे-धीरे सरकारी कामकाज से अंग्रेजी को हटाया जाए। लेकिन संविधान को लागू हुए भी लगभग सात दशक हो चुके हैं, मगर इस दौरान किसी भी सरकार ने संविधान के निर्देशानुसार अंग्रेजी की जगह हिन्दी को स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ लोकजीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी का रुतबा बढ़ता गया। यह हमारे देश की बदनसीबी है कि आजादी के सात दशक से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी भाषा के मामले में हम भारत के लोग आजाद नहीं हैं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद आजाद भारत में हिन्दी को उसका उचित स्थान नहीं मिल सका। और तो और हिंदी को वह स्थान भी नहीं मिल सका, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं और संविधान निर्माताओं ने उसे प्रदान किया था। हमारे संविधान की मंशा के मुताबिक कायदे से तो हिन्दी को 1965 में ही केंद्र सरकार की भाषा बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके काफी पहले ही दक्षिण के एक-दो राज्यों में हिन्दी के विरोध में मामूली से उपद्रव होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐतिहासिक आश्वासन दे डाला था कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। नेहरू को दिवंगत हुए करीब छह दशक हो गए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि हिन्दी भले ही न थोपी जाए पर अंग्रेजी को देश पर क्यों थोपा जा रहा है? सवाल यह भी है कि अंग्रेजी क्यों अभी तक पटरानी बनी हुई है और हिंदी क्यों दासी बनी अपनी दुर्दशा पर विलाप कर रही है? कोई माने या न माने पर नेहरू के जमाने से लेकर आज तक किस्सा यही है कि भाषा के सवाल को राजनीति के तहखाने में डाल दिया गया है। डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे जिन-जिन लोगों ने हिन्दी या भारतीय भाषाओं के सम्मान का सवाल उठाया, उनको या तो हिकारत से देखा गया या फिर पीछेदेखू करार देकर उनका उपहास उड़ाया गया। अब तो हालत यह हो गई है कि हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए राजनीतिक स्तर पर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक दलों का आम कामकाज भी अंग्रेजी में ही होता है। यहां तक कि भारतीय संस्कृति को लेकर रात-दिन चिंतित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के उसके अन्य सहोदर संगठनों की चिंता के दायरे में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बचाने का सवाल कभी नहीं आता। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों के एजेंडा से हिन्दी का सवाल अब पूरी तरह गायब हो गया है। सारे राजनेताओं के लिए अब हिन्दी महज नारेबाजी और भाषणबाजी यानी चुनाव प्रचार और वोट मांगने की भाषा बन कर रह गई है। कुल मिलाकर हिन्दी को उसकी खोई हुई हैसियत लौटाने की राजनीति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसका स्थान अब हिन्दी की भावुकता ने ले लिया है। यह भावुकता हिन्दीभाषियों और हिन्दीप्रेमियों को श्अह सुबह कभी तो आएगी की तर्ज पर तसल्ली देती रहती है कि कभी न कभी हिन्दी के दिन बहुरेंगे। यह भावुकता सरकारी संसाधनों से होने वाली विश्व हिन्दी सम्मेलनों जैसी नौटंकियों में पूरी शिद्दत से अपने घटिया स्वरूप में उभरकर सामने आती है, जिनमें तथाकथित साहित्यिक रुझान वाले कुछ राजनेता, कुछ नौकरशाह और सत्ता के गलियारों पैठ रखने वाले कुछ जुगाड़ू साहित्यकार तथा पत्रकार सरकारी पैसे पर विदेश का सैरसपाटा कर आते हैं।

संपूर्ण समाधान दिवस एसडीएम की उपस्थिति में हुआ संपन्न

संक्रमण के दृष्टिगत छह माह के अंतराल के बाद जारी हुआ तहसील दिवस

मेजा, प्रयागराज। शासन द्वारा निर्देशन के क्रम में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया।

बता दे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत संपूर्ण समाधान दिवस पर रोक लगा दी गई थी। शासन द्वारा पिछले दिनों समाधान दिवस जारी करने के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस पर एहतियात के तौर पर प्रत्येक फरियादियों की स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजर के साथ उचित दूरी की व्यवस्था किया गया था। मौके पर जानकारी के अभाव में फरियादियों की भीड़ काफी कम दिखी। एसडीएम मेजा, रेनू सिंह ने आए हुए

फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए, निराकरण का आश्वासन दिया।

फरियादियों की सूची में मांडा ब्लॉक के धराव गजपति से आए प्रार्थी ने पंचायत भवन निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा राजनीति करते हुए, गलत स्थान पर मानक के विपरीत निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत की। शिकायतकर्ता के मुताबिक आहोपुर गांव मे सार्वजनिक भवन प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। राजस्व गांव नेवढिया कला में ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध है, जबकि धराव गजपति में कोई सार्वजनिक भवन नहीं है। वही गांव में रास्ते का भी अभाव है। पट्टे की भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। बताया कि धराव गजपति के ही काश्तकार राधेश्याम बींद, राजेश कुमार, रामलाल, राम सुंदर पुत्र स्वर्गीय जीत नारायण बिंद अपनी जमीन को पंचायत भवन हेतु खुशी से दान देने को तैयार है। शिकायतकर्ता ने उक्त स्थान पर पंचायत भवन निर्माण की मांग की है।

उक्त मौके पर तहसीलदार दीपिका सिंह व क्षेत्राधिकारी सच्चिदानंद ने संबंधित शिकायत पत्रों को संज्ञान में लेते हुए, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत संचालित पोषण माह

आंगनबाड़ी केंद्र पारा कुवर मजीठा पर माताओं को किया जागरूक

बाराबंकी। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत संचालित पोषण माह के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केंद्र पाराकुँवर मंजीठा पर माताओं को जागरूक किया गया। बच्चों को भोजन से आवश्यक तत्व मिलते रहें इसके लिए स्वादिष्ट भोजन तथा बीमारी के समय विशेष भोजन विषयक चर्चा की गयी। आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा चार्ट के माध्यम से भी समझाते हुए बताया गया कि बच्चा स्वस्थ रहे और तेज दिमाग वाला रहे ये हर माँ बाप सोचते हैं पर बच्चे के लिए जो जरूरी है वो पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की सचिव क्रांति देवी, रुक्मणि देवी, शशि रावत, पिंकी, प्रीति, गुड़िया, शांती, संध्या रावत, मीरा देवी, सरिता देवी, सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं।

भ्रष्टाचार अन्याय और शोषण के विरुद्ध में शीघ्र जागरूकता अभियान लाया जाएगा

बाराबंकी। भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध प्रदेश में शीघ्र ही जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। भारतीय समाज सेवा संघ के नव मनोनीत प्रदेश महासचिव, रमाकांत मिश्र ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिये ।

उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर यादव ने उन्हें प्रदेश महासचिव का दायित्व सौंपा है, उसे मैं पूरी कर्मठता से निभाउंगा।कोरोना काल मे अस्पतालों द्वारा मनमाने ढंग से मरीजों को लूटा जा रहा है, गांवों में प्रधानों द्वारा सरकारी जमीनों का पट्टा मनमाने ढंग से किया जा रहा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर हम आम जनता की सेवा करेंगे।

आवास योजन के पात्र एवं सूची मे नाम अंकित होने के बाद भष्ट अधिकारियों ने नहीं दिया आवास

बाराबंकी। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को आवास मुहैया करा रही वही भष्ट अधिकारियों के रवैये के कारण नही मिल पा रहा लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली कर अपात्रों को पात्र बनाकर आवास बांटे जा रहे हैं। मामला विकासखंड बनीकोडर के अंतर्गत ग्राम दयाराम पुरवा जेठबनी निवासी जाकिर अली पुत्र मुस्तफा अहमद का नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में चयनित हुआ था इन पात्रों का नाम चयन सूची से गायब कर दिया गया है पीड़ित ने बताया कि उनकी शिकायत को हर बार पक्का मकान दिखाकर निस्तारित कर दिया गया,जबकि वह आज भी अपने परिवार के साथ मिट्टी के बने कच्चे घर में रह रहा है पीड़ित ने अब तक जिले से लेकर सभी उच्च अधिकारियों से लिखित मौखिक शिकायत किया लेकिन जांच अधिकारी ने बिना मौका देखे उन लोगों को पांच कमरे वाला पक्के मकान का मालिक बना दिया पीड़ित ने कहा कि उनका नाम आवास पात्रता सूची से पृथक कर दिया गया है उनके घरों की निष्पक्ष जांच मौके पर भेजकर करवा ली जाए।

एक तरफ सरकार जहां पर गरीबों के लिए आवास और अन्य तरह की सुविधाओं के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाती हैं तो दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी गरीबों का लगातार शोषण कर रहे हैं ब्लाक बनीकोडर में जब से खंड विकास अधिकारी डॉ आदित्य तिवारी की तैनाती हुई तब से भष्टाचार अपने चरम सीमा पर है गरीबों की सभी योजनाओं में प्रधान व सचिव से मिलकर गरीबों को मिलने वाला लाभ नहीं दे रहे हैं ग्राम दयाराम पुरवा मजरे निवासी जाकिर अली पुत्र मुस्तफा अहमद एक निहायत गरीब व्यक्ति हैंपीड़ित ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास सूची में क्रमांक संख्या 26 पर नाम दर्ज भी है लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया जो कि ग्राम प्रधान और खण्ड विकास अधिकारी की मिलीभगत के कारण इनका नाम सूची में होते हुए भी ग्राम प्रधान माधुरी देवी व उनके पति राजकुमार जो कि सरकारी प्रधानाध्यापक है पूरा काम वही देखते हैं ब्लॉक के करीब ही ड्यूटी करते हैं पूरा दिन ब्लॉक में ही रहते हैं उन्होंने जाकिर अली के नाम से जो आवास आया था उसको किसी दूसरे को आवंटन कर दिया और इस तरह से काफी हेराफेरी की गई जिनके घर पक्के हैं उन्हीं लोगों से पैसा लेकर आवास दिया जा रहा है जो ग्राम प्रधान ग्राम सचिव और खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी के संलिप्त होंने के कारण ऐसा संभव बताया गया है ये अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर गरीब लोगों के आवास दूसरे अमीर व्यक्तियों को देते रहते हैं पीड़ित जाकिर अली ने बताया कि 2016 से लेकर आज तक ऊपर से लेकर सभी अधिकारी को एप्लीकेशन दिया लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं आई,तो वही खण्ड विकास अधिकारी डॉ आदित्य तिवारी के कार्यालय में जाकर कहा तो साहब कुर्सी के मद में पीड़ित को कार्यालय से भागते हुये कहा कि एप्लीकेशन देते रहो और हम आख्या लगवाते रहंगे और दुबारा हमारे कार्यालय में कदम न रखना पीड़ित ने बताया पीड़ित ने बताया कि ग्राम सचिव वी पी सरोज के मनीष सिंह के सहायक निर्मल कुमार रावत एवं रणविजय पाल द्वारा उनसे ?25000 मांगा गया और कहा यदि तुम्हें आवास चाहिए तो तुम ?25000 की व्यवस्था करो वरना एप्लीकेशन देते रहो मैं आख्या लगाता रहूंगा मैं जो लिख कर दूंगा वही अधिकारी मानेंगे कोई जांच करने नही आयेगा।

पीड़ित 2016 से लेकर आज तक उच्च अधिकारी बाराबंकी से लेकर प्रशासन स्तर पर रजिस्ट्री तहसील दिवस एवं अन्य सभी जगहों पर शिकायत करने के बावजूद आज तक पीड़ित गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है अब सवाल यह उठता है कि ब्लॉक बनीकोडर में कई साल से तैनात खंड विकास अधिकारी अपनी तानाशाही से गरीबों व पात्र लोगों की आवास शौचालय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित करने के लिए सरकार ने नियुक्त किया है,किन वजहों से बार बार शिकायत के बावजूद सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही नही हो रही है। जिससे इनकी तमाम तरह की भ्रष्टाचार में संलिप्त एवं ग्राम प्रधान ग्राम सचिव आदि लोगों से मिलीभगत से गरीबो की योजनाओं की हेराफेरी हो रही है।

पैसे ना देने पर ब्लाक के अधिकारियों ने कच्चे मकान को दिखा दिया पक्का

पीडित ने शासन प्रशासन से 4 दर्जनों से अधिक की शिकायत लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर शासन प्रशासन को भी कर दिया गुमराह

भाजपा ने 70 वृद्ध जनों में किया चश्मे का वितरण

बस्ती। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर मनाये जा रहे सेवा सप्ताह की कड़ी में साऊंघाट विकास खण्ड के कडर मंदिर पर वृद्ध जनों में निःशुल्क चश्मे का वितरण जांच कराकर किया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक दयाराम चौधरी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष मनोज ठाकुर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि पात्रों में चश्मे का वितरण पुनीत कार्य है। वृद्धावस्था में इसकी जरूरत पड़ती है। जिन वृद्ध जनों को चश्मा मिला है निश्चित रूप से वह उनके लिये उपयोगी साबित होगा। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संकट काल में चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गरीबों को सर्वाधिक मदद की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महेश शुक्ल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सेवा और समर्पण में विश्वास करते हैं।

चमनगंज झूसी में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गयी

प्रयागराज। चमनगंज में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री के बारे में लगातार सूचना मिलने पर ए.के. सिंह उप आबकारी आयुक्त के निर्देश पर एस.बी.वोडवेल जिला आबकारी द्वारा आबकारी क्षेत्र 5, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह तथा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 विजय प्रताप यादव, एसएसएफ श्रीमती नेहा सिंह की टीम बनाकर सूचना की पुष्टी होने पर टीम द्वारा मुकेश जायसवाल के घर पर दबिश की कार्यवाही की गयी और मौके पर विडीज लाइम ब्रांड की 170 पौवा (200 एम0 एल0 तीर्वता 36 प्रतिशत V/V) नकली रैपर, शीशियां,800 नकली ढक्कन, 18 खाली पेटी, एक जेरिकेन में 30 लीटर स्प्रिट व भारी मात्रा में शराब (34 ली0) एवं चार पहिया वाहन सं0 यू पी 72 बी डी- 0428 की बरामदी की गयी। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना- झूंसी में आबकारी अधिनियम की धारा60/72 एवं आईपीसी की धारा 419,420,467, 468 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नवागत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

संत कबीर नगर। नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में नव निर्मित खलीलाबाद तहसील सभागार में कोविड-19/कोरोनो संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन करते हुये सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने एक-एक फरियादी/शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत तौर पर रूबरू होते हुये उनकी शिकायत सुनी तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को अविलम्ब एवं गुणवत्तायुक्त समाधान कराने का भी निर्देश भी दिया। उन्होंने प्राप्त सभी शिकायतों एवं लम्बित प्रकरणों का समय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश देते हुये कहा कि अधिकारीगण आवश्यकतानुसार स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करें तथा शिकायतकर्ता को सुनकर आपसी सुलह समझौतों से विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक भू-सम्पत्तियों चकमार्गों आदि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। शिकायती मामलों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करा दिया जाये तथा अधिक समय से लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के कारणों का भी उल्लेख किया जाये। समाधान दिवस में मिले संदर्भों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच के लिये औचक रूप से शिकायतकर्ताओं से उनके मोबाइल नम्बर पर बात भी की जाये। आज आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 मामले प्रस्तुत किये गये, जिसमें 04 मामलों का मौके पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रयास से मौके पर तत्काल निस्तारण करा दिया गया। आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह, उप जिलाधिकारी खलीलाबाद राज नारायण त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

ओबीसी महासभा प्रयागराज द्वारा उपजिलाधिकारी करछना को दिया गया ज्ञापन

प्रयागराज। ओबीसी महासभा प्रयागराज जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने सहित अन्य मांगों के संबंध में उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। सोमवार को ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने करछना तहसील पहुंच कर उपजिलाधिकारी आकांक्षा राणा से मुलाकात की । उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी करछना को सौंपा।

ओबीसी महासभा ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने के लिए जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम अविलंब जोडा जाए। इसके अलावा मंडल आयोग की अनुशंसाओ को पूर्णत लागू किया जाए। ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात वर्ग के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिक एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण की जाए। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। ओबीसी आरक्षण में अंसवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तो को समाप्त किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी विभागों में ओबीसी के रिक्त पदों, बैकलॉग को अतिशीघ्र भरा जाए।

मुख्यमंत्री द्वारा वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विकास कार्यो की मण्डलीय समीक्षा बैठक

संत कबीर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियों काफ्रेसिंग के माध्यम से जनपद में रू0 10 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य लागत की परियोजनाओं/निर्माण कार्यो सहित जनपद में संचालित लाभार्थीपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में प्रगति, किसानों हेतु खाद, बीज एवं पानी की उपलब्धता सहित कोविड-19/कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु किये जा रहें कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गयी। वीडियों काफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के राज्यमंत्री श्रीराम चैहान, विधायकगण दिग्विजय नारायण जय चौबे, एवं राकेश सिंह बघेल से निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में बिन्दुवार फीड बैक प्राप्त किया उनके विधानसभाओं के चैमुखी विकास में शिक्षा, सड़क, स्वच्छ पेयजल, अस्पताल, आदि की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया एवं शासन स्तर से उसे पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को जनपद में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। जनपद के विकास की गति में तेजी लाने का निर्देश देते हुए परियोजनाओं और विकास कार्यो को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानक के अनुसार पूर्ण कराने जाने का निर्देश दिया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी परियोजना/निर्माण कार्य के निर्धारित अवधि में पूर्ण होने पर लागत में कमी आने के साथ-साथ जनसामान्य को विकास योजनाओं का ससमय लाभ मिलता है तथा शासन एवं प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने निर्धारित समीक्षा बिन्दुओं/विकास कार्यो के प्रगति की अद्यतन स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत किया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, निर्माण, लाभार्थीपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन एवं जनसामान्य के बहुआयामी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए शासन स्तर से धनराशि की कोई कमी नही आने दी जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता पाये जाने पर सम्बंधित की जबावदेही सुनिश्चित करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें कोरोना सक्रमण से बचाव करते हुए, पूरी सतर्कता एवं सावधानी अपनाते हुए विकास कार्यो को तीव्र गति से सम्पन्न कराने हेतु पूरे मनयोग से कार्यो/कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता के साथ लगे रहना है। उन्होंने कोविड-19/कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराये जाने के भी निर्देश दिये। ''दो गज की दूरी-मास्क है जरूरी'' के साथ-साथ सेनेटाइजर एवं साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। कोविड कन्ट्रोल सेन्टर के साथ-साथ एल-1/एल-2 अस्पताल को निरंतर सक्रिया रखा जाए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास कार्यो/परियोजनाओं में निरंतरता एवं प्रगति के आधार पर आवश्यकतानुसार मासिक पाक्षिक/साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

तस्करी के लिये ले जाया जा रहा भारी मात्रा गांजा वाहन सहित बरामद, छः अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

विध्याचल। मीरजापुर विध्याचल थाना के अन्तर्गत सोमवार को संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों के सघन चेकिंग के दौरान थाना विन्ध्यांचल व स्वाट/ एसओजी की संयुक्त टीम नें दुधनाथ चुंगी तिराहे के पास मीरजापुर की ओर से प्रयागराज की तरफ जा रही इनोवां क्रिस्टा नं0- क्क32 ॥स्र 6067 के ठीक पीछे चल रही डीसीएम वाहन नंबर क्क15 श्वञ्ज 2912 को रोकने का प्रयास किया गया, तो इनोवां क्रिस्टा में सवार 04 व्यक्ति तथा डीसीएम में सवार 02 व्यक्ति कुद कर भागने लगे, जिनको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया, भागने का कारण पूछने पर पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा बताया गया, कि हमारी डीसीएम में तिरपाल के नीचे नारियल ढ़ाभ कुछ खाली कुछ भरे है,तथा उनके डंढल के नीचे बोरो में तथा इनोवा गाड़ी के डिग्गी में गांजा रखा है, पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनो वाहने की तलाशी ली गयी तो डीसीएम से 10 बोरियों में 41 बंडल तथा इनोवा किस्ट्रा गाड़ी की डिग्गी से 03 बंडल अवैध गांजा बरामद किया गया, इस प्रकार कुल 02 कुंतल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर, सभी 06 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया, अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना विन्ध्यांचल पर मु0अ0स0- 145/2020 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामद वाहनो को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम मे सीज किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के संबंध में उनके जनपद से पता किया जा रहा है। विशेष विवरण मजीद पूछताछ अभियुक्तगण गिरफ्तार अभियुक्तगण से गांजा के सम्बन्ध में पूछने पर बताया गया कि गांजा हम लोग उड़ीसा से सस्ते दाम में गांजा खरीद कर मथुरा तथा आस पास के जनपदो में उचे दाम पर बेच कर आर्थिक लाभ कमाते है,अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार शर्मा तथा विद्याभुषण शर्मा द्वारा गांजा तथा इन गाड़ियों के मालिक के संबंध में पूछने पर बताये कि विनोद चौधरी इनोवा चालक व जितेन्द्र सिंह व मनीष डीसीएम चालक है, तथा मुकेश कुमार हमलोगो का गांजा के कारोबार में सहयोगी है, गांजा ढ़ोने व सप्लाई में अन्य सामानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा

लाभ होता है, तथा इस कारोबार में हम लोग लगभग 02 वर्षो से है।गिरफ्तार अभियुक्त विनोद चौधरी पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी अकोस थाना बलदेव जनपद मथुरा। उम्र-29 वर्ष। मुकेश कुमार पुत्र बृजलाल निवासी गौरही थाना इगलास जनपद अलीगढ़। उम्र-32 वर्ष। शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी भगवानगढ़ी थाना इगलास जनपद अलीगढ़। उम्र-32 वर्ष विद्याभुषण शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा निवासी सेखड़ा थाना इमचोटी जनपद मेरठ। उम्र-47 वर्ष जितेन्द्र पुत्र बनारसी लाल निवासी नगलामान सिंह थाना गाधीपाक जनपद अलीगढ़। उम्र-29 वर्ष मनीष पुत्र राघवेन्द्र निवासी अकरावत थाना लोढ़ा जनपगद अलीगढ़। उम्र-20 वर्ष गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण थाना विन्ध्यांचल पुलिस टीम प्र0नि0 शेषधर पाण्डेय थाना विन्ध्यांचल व0उ0नि0 केदारनाथ मौर्या थाना विन्ध्यांचल उ0नि0 भारत भुषण सिंह चौ0प्र0 गैपुरा व उनकी टीम।स्वाट / सर्विलांस टीम उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट टीम व उनकी टी। एस0ओ0जी0 टीम उ0नि0 जयदीप सिंह एस0ओ0जी0 व उनकी टीम।उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ?15000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया गिरफ्तार।

चोरी व लूट के मोबाईल के साथ बड़ी संख्या में चोर गिरफ़्तार

■ महिला व नबालिग भी गिरोह में शामिल ■ लगभग तीन लाख की क़ीमत के चौबीस मोबाईल बरामद

गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र पर क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह द्वारा बताया गया की प्रभारी निरीक्षक रामज्ञा सिंह के नेतृत्व में सोमवार की रात आठ बजे के क़रीब पाँच शातिर अंतर्राज्यीय चोरो को गिरफ़्तार करने मे सफलता मिली है।

सोमवार को थाना क्षेत्र के सनी श्रीवास्तव गोरखनाथ पूल के नीचे सब्ज़ी मंडी मे सब्ज़ी ले रहे थे तभी उनका मोबाईल लेकर चोर फ़रार हो गये उनमे से एक चोर को सनी श्रीवास्तव ने देख लिया था शाम को उन्होंने चोर के हुंमायुपुर में दिखने की सूचना गोरखनाथ थाना प्रभारी को दी जिसपर प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ लगकर रात में आठ बजे के क़रीब हुंमायुपुर उत्तरी हरिजन बस्ती में देवानंद के मकान में किराये पर रह रहे चोरों को धर दबोचा पुछताक्ष करने पर पता चला की सभी पश्चिम बंगाल व झारखंड के रहने वाले है निम्न अभियुक्तों के नाम रवीउल्लाह पुत्र जमाल शेख,जमीरुलशेख़ पुत्र दविरुद्दीन, राहुल कुमार पुत्र संजय व एक महिला संतोषी देवी उर्फ़ वैशाली पत्नी अर्जुन महतो साथ में एक नाबालिग लड़का मुन्ना कुमार पुत्र संजय लोनिया है। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने बताया की अभियुक्तों द्वारा भिन्न भिन्न स्थान जैसे सब्ज़ी मंडी, दुकानो भीड़भाड़ जैसे आदि जगहो पर किसी न किसी बहाने सटकर मोबाइल चोरी कर एक जगह इकट्ठा होकर दूसरों प्रांतो मे ले जाकर बेचते है और इन कार्यों में छोटे उम्र के बच्चों का इस्तेमाल करते है। उपरोक्त अभियुक्तों के पास से चौबीस मोबाईल,एक तमंचा ज़दि कारतूस सहित 12 बोर एक धारदार गडासा बरामद हुआ। चौबीस मोबाईल की क़ीमत लगभग तीन लाख रुपए बतायी जा रही है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध 379,411,413 आईपीसी व 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार अलग अलग मुक़दमे गोरखनाथ थाने में दर्ज है। चौबीस मोबाईल में एक मोबाईल की शिनाख्त हो चुकी है। उपरोक्त मुल्जिम मोबाईल कहाँ कहाँ और किन लोगों को बेचते थे इसकी जाँच की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश

बस्ती। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुधौली चीनी मिल का गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान अगले पेराई सत्र के पूर्व कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि चीनी मिल के प्रदूषित केमिकल आमी नदी में गिराने से रोके ताकि पानी प्रदूषित न हो। उन्होंने रुधौली चीनी मिल के गोडाउन का तत्काल जांच करा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती मंडल के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि गन्ना किसानों के बकाए 42 करोड़ के भुगतान के लिए बस्ती एवं वाल्टरगंज चीनी मिलों को शीघ्र नीलाम कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2018-19 में 52 सड़कों के टेंडर एवं गुणवत्ताविहीन कार्यों में संबंधित दोषी अभियंताओं से वसूली करने का निर्देश दिया है।

पैकोलिया पुलिस ने 1.2 किलो अवैध गांजे के साथ किया गिरफ्तार

बस्ती। पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया शिवाकांत मिश्र मय फोर्स के दिनांक 14/09/2020 को देखभाल क्षेत्र भ्रमण/ संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहनों की चेकिंग के लिए मरवाटिया बाज़ार से हसीनाबाद जा रहा था तो एक व्यक्ति अगया बुजुर्ग जाने वाले मोड़ पर स्थित पुलिया पर बैठा था हम पुलिस वालों को देख कर अगया बुजुर्ग गांव की तरफ भागने लगा जिसको दौड़ा कर समय 5:05 बजे पकड़ लिया गया उसके पास से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कल्लू उर्फ दुर्गेश पुत्र प्रदीप निवासी गड़ाहादल थम्मन थाना पैकोलिया जनपद बस्ती बताया । जिसके खिलाफ मु0अ0सं0 121/2020 धारा 8/20 NDPS ACT मे मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

छावनी पुलिस ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

बस्ती। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक छावनी सौदागर राय के कुशल नेतृत्व में थाना छावनी पुलिस द्वारा मंगलवार को थाना छावनी अंतर्गत राम जानकी मार्ग के पास से मु0अ0सं0 143/20 धारा 323,504, 506, 325, 336, 308 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त गण क्रमशः 1.अरुण यादव 2.राम पवन उर्फ पवन पुत्र गण श्याम सुंदर ग्राम शंकरपुर थाना छावनी जनपद बस्ती तथा 3.राजेश व 4.राज कुमार पुत्र रामलाल ग्राम शंकरपुर थाना छावनी जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संपूर्ण समाधान तहसील दिवस महेवा मंडी में आए हुए फरियादियों की समस्या को सुना गया

गोरखपुर/सोमवार को सदर तहसील में लगे स्वास्थ्य कैंप में जांच के दौरान सात कर्मचारियों के संक्रमित मिलने की वजह से सदर तहसील कार्यालय को बंद कर सैनिटाइजेशन का किया गया लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महीने के पहले व तीसरे मंगलवार को पुनः संपूर्ण समाधान तहसील दिवस शुरू कर जनता की समस्याओं को अधिकारीगण संपूर्ण समाधान दिवस में सुनेंगे सदर तहसील में कोरोना संक्रमित 7 मरीज मिलने की वजह से जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सर गौरव सिंह सोगरवाल ने सदर तहसील दिवस का आयोजन महेवा गल्ला मंडी में आए हुए फरियादियों की समस्या को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सुना कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 6 महीने से बंद चल रहे तहसील दिवस शुरू होने से आम जनता में खुशी की लहर है कि अब तहसीलों में समस्याओं के समाधान हेतु तहसील खुला रहेगा जिससे जनता की समस्याओं का निराकरण समय से हो सकेगा इसके पहले 18 मार्च को संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन हुआ था। महीने में दो दिन (पहले और तीसरे मंगलवार को) आयोजित होने वाले तहसील दिवस को लेकर कोरोना संक्रमण की वजह से विशेष सतर्कता बरती जा रही हैं। तहसीलों में सभागारों की जगह खुले स्थान पर आयोजन होगा। एक दिवस पर 50 फरियाद ही सुनी गयी टोकन सिस्टम लागू रहा फरियादियों को अनिवार्य तौर पर मॉस्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना जरूरी रहा बरसात होने की वजह से ही फरियादियों की संख्या कम रही अब देखना है कि 6 महीनों से बंद पड़े तहसीलों के कोर्ट जनता की सुविधा के लिए पुनः चालू होते हैं कि नहीं क्योंकि दूर दराज से आम जनता तहसीलों का चक्कर लगाकर परेशान होकर वापस चली जाती है। संपूर्ण समाधान तहसील दिवस में प्रमुख रूप से ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दिक्षित नया तहसीलदार नीलम तिवारी नायब तहसीलदार सुमित सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

राज्यसभा का उप सभापति चुने जाने पर पार्टी पदाधिकारियों ने दी बधाई

बस्ती। जनता दल यूनाइटेड के सांसद डा. हरिवंश नरायन सिंह को राज्यसभा का दोबारा उप सभापति चुने जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हे बधाई दिया है। प्रदेश सचिव प्रवीन कुमार चौधरी ने पार्टी नेतृत्व को बधाई देते हुये कहा है कि डा. हरिवंश नरायन सिंह के मार्गदर्शन में पार्टी व्यवहारिक और सैद्धान्तिक रूप से मजबूत होगी। डा. हरिवंश नरायन सिंह को बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से मनीष कुमार श्रीवास्तव, रोहित वर्मा, रामकेश चौधरी, इन्द्रजीत, रामफेर, अनिल कुमार, धर्मेन्द्र चौधरी, बृजनंदन चौधरी, कुंदन चौधरी विजय चौधरी चौरसिया आदि शामिल रहे।

भाजपा ने 70 वृद्ध जनों में किया चश्मे का वितरण

पीएम मोदी के जन्म दिन पर सेवा सप्ताह में होंगे कई आयोजन- महेश शुक्ल विधायक दयाराम ने दिया कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

बस्ती। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर मनाये जा रहे सेवा सप्ताह की कड़ी में साऊंघाट विकास खण्ड के कडर मंदिर पर वृद्ध जनों में निःशुल्क चश्मे का वितरण जांच कराकर किया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक दयाराम चौधरी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष मनोज ठाकुर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि पात्रों में चश्मे का वितरण पुनीत कार्य है। वृद्धावस्था में इसकी जरूरत पड़ती है। जिन वृद्ध जनों को चश्मा मिला है निश्चित रूप से वह उनके लिये उपयोगी साबित होगा। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संकट काल में चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गरीबों को सर्वाधिक मदद की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महेश शुक्ल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सेवा और समर्पण में विश्वास करते हैं। यही हमारी शक्ति है। उन्होने सरकार द्वारा चलाये जा रहे अनेक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिये।

कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल ने किया, कहा कि एक सप्ताह तक पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कामेन्द्र चौहान, प्रधान वीरेन्द्र चौधरी, रामचरन चौधरी, वैभव पाण्डेय, अखण्ड प्रताप सिंह, अजय कुमार श्रीवास्तव, बच्चालाल चौधरी, कलाऊ चौहान, श्याम भवन, भोली पाण्डेय, चन्द्रमणि पाठक, शैलेन्द्र राना, अंकुर श्रीवास्तव, राजन पाण्डेय, उदयभान चौधरी, पिन्टू चौधरी, लालमन चौहान, जय प्रकाश पाण्डेय, ओम जी पाण्डेय, राधेश्याम, रामभवन, राघव पाण्डेय, लालचंद, दीपक नायक के साथ ही चश्मे के लिये आये वृद्ध जन उपस्थित रहे।

गोरखपुर रामगढ़ झील के वेटलैंड का दायरा जल्द होगा सार्वजनिक इन कामों पर लगेगी रोक

गोरखपुर/ रामगढ़ झील प्रदेश की पहली अधिसूचित वेटलैंड बनने की ओर एक कदम और बढ़ चली है। 15 जून की प्रारंभिक अधिसूचना के बाद आई रिकार्ड 206 आपत्तियों की सुनवाई के बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेज दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि माह के आखिर तक उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रिपोर्ट पेश हो जाएगी। 15 जून की प्रारंभिक सूचना के बाद 30 जून तक प्रमुख सचिव वन एवं रावण ने प्रभावित लोगों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की थी। तकरीबन 206 दावे और आपत्तियां मिली जिन पर सुनवाई एवं निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में गठित जिला आर्द्रभूमि प्राधिकरण को भेजा गया। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार प्राधिकरण ने सभी आपत्तियों का निस्तारण कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इस माह के आखिर तक उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण मैं रिपोर्ट की समीक्षा हो जाएगी। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित इस प्राधिकरण की मंजूरी के बाद वापस जिला आर्द्रभूमि प्राधिकरण को अंतिम अधिसूचना का ड्राफ्ट बनाने के लिए भेजा जाएगा। जिला ड्राफ्ट बनाकर पुनः??शासन को भेजेगा जहां से न्याय विभाग होते हुए एयरड्राप अंतिम प्रकाशन के लिए राज्यपाल कार्यालय जाएगा। डीएफओ अविनाश कुमार का कहना है कि रामगढ़ झील के वेटलैंड के रूप में अधिसूचित होने के कई लाभ होंगे। झील अपने मूल स्वरूप में बनी रहेगी। आसपास के भूगर्भ जल का स्तर सुधरेगा। झील में मिलने वाली वनस्पतियां कार्बन और अवशोषित करेगी ही जैव विविधता का संरक्षण और सरवन होगा। झील के आसपास इन कामों पर लगेगी रोक अधिसूचना के बाद झील के अधिनियम दायरे में कोई नया उद्योग नहीं लग सकता। पुरानी कारों के विस्तार पर रोक होगी। इस दायरे में खतरनाक किस्म के कचरे, पॉलिथीन, नान बायोडिग्रेडिबल ठोस कचरे, गंदा पानी, अशोधित सीवेज के निस्तारण पर भी रोक होगी। नौकायन के लिए जेट्टी को छोड़कर किसी तरह के निर्माण पर रोक होगी।

जो धोखा देगा वह धोखा खाएगा आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है: रविंद्र मणि निषाद

गोरखपुर/ निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल मछुआ समुदाय के अगुआ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय निषाद के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी रविंद्र मणि निषाद के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गृहमंत्री भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गोरखपुर के मार्फत सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को नगर निगम लक्ष्मी बाई पार्क में सौंपा रविंद्र मणि निषाद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2015 में निषाद आरक्षण को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर कहा था कि बीजेपी की सरकार आई तो निषादों की लड़ाई सदन में उठाते हुए आरक्षण दिलाने का काम भाजपा सरकार करेगी आज प्रदेश एवं केंद्र दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है मगर आरक्षण का वादा सिर्फ वादा बनकर रह गया है अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपने वादा को पूरा करते हुए आरक्षण का लाभ मछुआ समुदाय को दे देना चाहिए श्री निषाद ने आगे कहा कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनवाए थे वह हमारे आरक्षण लागू करें सभी सांसदों को ज्ञापन दिया गया ताकि केंद्र के गृह मंत्रालय से जो लाभ दूसरी जाति को मिलता है उसी तरह अब निषादों को मिले जिन्हें अंग्रेजों ने उजाड़ा था उन्हें हिस्सा देकर बसाया जाए मछुआ समुदाय शहर देशहाभिमानी रहा है सबका साथ सबका विकास भाजपा ने वादा किया था वह पूरा करें या धोखा खाया हुआ समाज अब जाग गया है और जो धोखा देगा वह धोखा खाएगा आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे हम लेकर रहेंगे। ज्ञापन लेते समय क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला क्षेत्राधिकारी एलआईयू अरुण सिंह सहित कैंट व कोतवाली की फोर्स मौजूद रही।

रिटायर सैनिक ने दिया राम मंदिर निर्माण में इक्कीस हजार का चेक

महराजगंज। नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरवाकला निवासी रामराज प्रसाद त्रिपाठी ने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर

निर्माण में इक्कीस हजार रुपए का चेक देकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में चर्चा बना हुआ है लोगों का कहना है कि सेना का जवान वास्तव में मरते दम तक देश का सच्चा सिपाही होता है। रिटायर जवान रामराज त्रिपाठी जो इंडियन आर्मी में नायक के पद पर तैनात थे। इन के इस कार्य को लेकर लोग खूब सराहना कर रहे है।

फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तिवारीपुर पुलिस ने कराई मुनादी

गोरखपुर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार के द्वारा चलाये जा रहे फरार अपराधियो की धर पकड़ के क्रम में आज तिवारीपुर थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे। कामरान कुरेशी पुत्र इकराम कुरैशी निवासी जाफरा बाजार के घर पुलिस ने मुनादी कराई गई। और नोटिस चस्पा किया गया। तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि कामरान कुरैशी के खिलाफ तिवारीपुर थाने पर अपराध संख्या 323/ 2019 धारा 302 307 506 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत था। जो काफी समय से फरार चल रहा है। आज आरोपी के घर पर मुनादी कराई गई है। और नोटिस चस्पा किया गया इसके बाद भी अगर आरोपी एक माह के अंदर न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपलब्ध नहीं होता है तो जल्द से जल्द कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

वीआईपी कोटे से कंफर्म टिकट के बाद भी स्टेशन से लौटा दिए गए यात्री

गोरखपुर/ रेलवे के वीआईपी कोटे से कंफर्म टिकट के आठ यात्रियों को वेटिंग कहकर रेलवे स्टेशन के गेट से ही वापस कर दिया गया। मामले की जानकारी जब रेलवे प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई।जानकारी के मुताबिक, 02591 गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस के यात्री सोमवार को सुबह से ही स्टेशन पहुंचने लगे। आठ ऐसे यात्री थे जिनका टिकट एस-3 कोच में 18, 19, 20, 21, व 26, 27, 28 व 29 नंबर के बर्थ रेलवे के वीआइपी कोटे से आरक्षित था।प्लेटफार्म पर प्रवेश करते समय गेट पर खड़े टिकट परीक्षकों को उन्होंने टिकट दिखाया। दूर से ही टिकट देखने के बाद टिकट परीक्षकों ने कहा कि वेटिंग है। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। गांव के कामगार यात्री निराश होकर गेट से ही लौट गए। टिकट परीक्षकों ने भी अपना चार्ट नहीं देखा और ना ही टिकट को चेक किया।आठों यात्री स्टेशन परिसर से बाहर निकलकर कंपनी मालिक को फोन करके शिकायत की तो मामला खुला। वहीं, कंपनी मालिक ने टिकट कंफर्म कराने के लिए रेलवे बोर्ड से ही पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को आवेदन कराया था।कामगार यात्री बंगलुरु स्थित कंपनी में काम करते हैं। प्रकरण जब रेलवे बोर्ड तक पहुंचा तो जांच शुरू कर दी गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गोरखपुर रेलवे ट्रैक पर मिली विवाहिता की लाश

गोरखपुर/ सहजनवा थाना क्षेत्र के सहजनवा मगर गेट संख्या 171 बी-2 के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की पहचान होने के बाद उसके ससुराल वालों ने जहां खुद किसी की बात कही अभी मायके वालों ने हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संत कबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र स्थित भीटी माफी गांव निवासी शैलेश कुमार की बेटी सोनी की शादी सहजनवा केपीटी रावत गांव निवासी सुग्रीव से हुई थी। रविवार की सुबह सोनी का शव की पहचान के बाद परिवार जनों को खबर किया। सोनी के पिता को जब जानकारी हुई तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है।

गाँव-गरीब, खेत-खलिहान और किसान के प्रति समर्पित रहा बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी का सार्वजनिक जीवन

बिहार राय के वैशाली जिले के महनार के हसनपुर घाट पर सोमवार /14 सितंबर को लोक नायक जय प्रकाश नारायण की पाठशाला से निकले छात्र व ब्रह्मा बाबा के नाम से मशहूर बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी को उनके छोटे पुत्र ने मुखाग्नि दी. देर शाम को हुई अंतेष्टि में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव , राय सरकार की ओर से बिहार सरकार की ओर से सूचना मंत्री नीरज कुमार , विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता , समाजसेवी , गणमान्य व्यक्ति व भारी संख्या में जनता की मौजूदगी थी जो रघुवंश बाबू की अपार लोकप्रियता की कहानी बयां कर रहे थे. मेरे जैसे लोग जिन्होंने शास्त्री जी को नहीं देखा , वे बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी के कार्य - व्यवहार से श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व की कल्पना करते थे. ईमानदारी - सादगी - साफगोई के पर्याय बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी को ग्रामीण विकास को सर्वोच प्राथमिकता देने के लिए सदैव याद किया जायेगा. श्रद्धेय रघुवंश प्रसाद सिंह जी राजनीति में आने से पूर्व सीतामढ़ी के एक कालेज में गणित विषय के प्रोफेसर हुआ करते थे . पढ़ने - पढ़ाने वाले स्वभाव के रघुवंश बाबू जे.पी. के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से प्रभावित होकर कर्पुरी ठाकुर के सानिध्य में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के झंडे तले सक्रिय हुए. आपात काल में वे मीसा के तहत गिरफतार हुए. बिहार सरकार में वे 1977 - 79 तक ऊर्जा मंत्री रहे. रघुवंश बाबू के आपात काल में ही बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव जी के निकट आये और तीन दशक से यादा समय तक उनके साथ एक लंबी राजनीतिक साझीदारी किया . डा.रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए

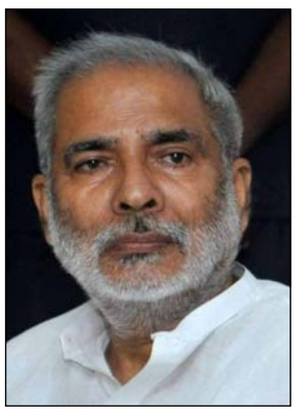

जहाँ से वे पांच बार सांसद बने . डा.मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने. सार्वजनिक जीवन में गाँव - गरीब , खेत - खलिहान और किसान के हक की लड़ाई लड़ने वाले और पेट - खेत की बात करने वाले रघुवंश बाबू ने मनरेगा जैसी योजना को लागू करने की वजह से इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बना लिया।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक
स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।
संपादक- कंचन सोलंकी
TITLE CODE- UPHIN48974
Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com
नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।